www.rashtratak.com twitter.com/rashtratak facebook.com/rashtratak @rashtratak

मूल्य ₹ 89

राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका

नई दिल्ली से प्रकाशित

राष्ट्र समाज

RNI No.: DELHIN/2014/56304

वर्ष-13 ▪ अंक-05 ▪ अगस्त 2026 ▪ पृष्ठ संख्या 52

आपकी आवाज़...

तिरंगा भारतीय स्वाभिमान, एकता और अमर... 06

जॉब नहीं तो सिंहासन हिलेगा 12

युवा आंदोलन

साझा नेतृत्व या बिखरती ताकत?

सकरनी
पेन्ट
रंग ऐसे
जो रंग जमा दें!
हर घर का
कंप्लीट सलूशन
सकरनी
UNIVERSAL STAINER
SAH CLASSIC
सकरनी
प्राइमर
Magic Grip
सकरनी
डिस्टेंपर पेन्ट
SUPER SHINE
EMULSION PAINT
FOR INTERIOR
सकरनी
इमल्शन पेन्ट
QUICK CLEAN
सकरनी
इमल्शन पेन्ट
CHARM
PRO PROTECT
Badalte Bharat Ka
Shilpkaar
SAKARNI PLASTER (INDIA) PRIVATE LIMITED
D Mall 405, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034
customercare@sakarni.com | +91-9810177365 | www.sakarni.com

संपादकीय

प्रमोद तिवारी संपादक

जब समाज शिक्षा को केवल नौकरी का साधन न मानकर चरित्र निर्माण का माध्यम मानेगा, तभी एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। देश की आर्थिक प्रगति में हमारे उद्यमियों, छोटे व्यापारियों और MSME क्षेत्र का योगदान अतुलनीय है।

समाज का राष्ट्र निर्माण में योगदान

राष्ट्र सिर्फ सरकारों या प्रशासनिक ढांचों से नहीं बनते, बल्कि समाज से आकार लेते हैं। ईंट, सीमेंट और बजट से इमारतें तो खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन उनमें जीवन वहां रहने वाले लोगों की सोच, संस्कार और आपसी सहयोग से ही आता है। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के सात दशकों बाद असली प्रगति का अहसास तब संभव है, जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे। और इन कर्तव्यों को सीखने की पहली पाठशाला हमारा समाज ही है। राष्ट्र निर्माण की नींव परिवार में रखी जाती है। मां पहली गुरु और पिता पहले आदर्श होते हैं। जब घर में बच्चे को सच बोलना, राष्ट्र का सम्मान करना और निष्ठा सिखाया जाता है, तो वही संस्कार आगे चलकर उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। इसी नींव को मजबूत करने का काम शिक्षक और हमारी शिक्षा प्रणाली करती है। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते, बल्कि चरित्र निर्माण करते हैं। जब समाज शिक्षा को केवल नौकरी का साधन न मानकर चरित्र निर्माण का माध्यम मानेगा, तभी एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। देश की आर्थिक प्रगति में हमारे उद्यमियों, छोटे व्यापारियों और MSME क्षेत्र का योगदान अतुलनीय है। 'मेड इन इंडिया' के संकल्प को धरातल पर उतारने वाले ये उद्यमी ही आत्मनिर्भरता की रीढ़ हैं। रक्षा उत्पादन से लेकर तकनीक तक में स्थानीय उद्योगों की बढ़ती भागीदारी देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में अहम कदम है। इस आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूती देने का काम हमारे किसान और मजदूर करते हैं। खेत में पसीना बहाता किसान और निर्माण में जुटा मजदूर बिना किसी शोर के राष्ट्र की प्रगति को गति देते हैं।

इन सभी घटकों को दिशा देने और जागरूक करने का काम मीडिया तथा राष्ट्र समाज जैसी विचारप्रधान पत्रिकाएं करती हैं। मीडिया का दायित्व केवल खबरें देना नहीं, बल्कि जन-कल्याणकारी विचारों का प्रसार करना और समाज को प्रेरित करना है। जब हम देश के वीरों की गाथाएं और जनहित की योजनाएं सामने लाते हैं, तो इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। हालाँकि, आज नशा, भ्रामक सूचनाएं (फेक न्यूज) और पर्यावरण क्षरण जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। इनका समाधान केवल सरकारी कानूनों से नहीं, बल्कि समाज के जागरूक प्रयासों से ही संभव है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ बड़े भाषण देना नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना है—नियमों का पालन करना, कर ईमानदारी से भरना, बेटियों को समान अवसर देना और पर्यावरण की रक्षा करना। हमें केवल शिकायतकर्ता बनने के बजाय समाधान का हिस्सा बनना होगा। यदि हर नागरिक अपने हिस्से का काम पूरी निष्ठा से करने का संकल्प ले, तो समाज स्वतः सशक्त हो जाएगा। 'मैं' से निकलकर 'हम' की भावना अपनाना ही राष्ट्र निर्माण की सच्ची शुरूआत है, क्योंकि एक सशक्त समाज ही समृद्ध राष्ट्र की रचना कर सकता है।

राष्ट्र समाज

RNI No.: DELHIN/2014/56304 ₹ 89

वर्ष-13, अंक-05, अगस्त 2026

पृष्ठ संख्या-52

प्रेरणा स्रोत

स्व.पुरुषोत्तम तिवारी, स्व.एन.के. लोहिया

मुख्य संरक्षक

विनीत कुमार गुप्ता

संरक्षक

बालमुकुन्द ओझा, त्रिवेणी नाथ तिवारी, हरिशंकर दुबे, संजीव गोयल

संपादक

प्रमोद तिवारी

सह संपादक

सुशील ओझा,आनंद दीप श्रीवास्तव, आचार्य श्रीकांत तिवारी

सलाहकार समिति

अशोक गुप्ता (सकरनी) सभाजीत पांडेय, एम. के त्रिपाठी, विपिन गोयल, संजीव गोयल, ऋषि मित्तल

कानूनी सलाहकार

अधिवक्ता बीपी पाण्डेय, गौरव भारद्वाज

ब्यूरो चीफ

किरन ओझा, पुनीत मिश्र, अखिलेश शर्मा, बसंत भट्ट, हरीश तिवारी, अशोक शर्मा

प्रसार

पुनीत मिश्रा-9911882767

विज्ञापन

आशुतोष तिवारी- 83682 72439

डिजाइन व प्रोडक्शन

एनएम मीडिया सॉल्यूशंस, दिल्ली

संपादकीय कार्यालयः मकान नं. 2, हपली मंजिल, पश्चिम एन्क्लेव, रोहतक रोड, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087

दूरभाषः 011-40105158, 9953772767

वेब : www.railhumrahi.com

ई-मेल : rastrasamaj@gmail.com

स्वत्वाधिकारी अपराइट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक प्रमोद तिवारी द्वारा एस-561, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-2, नई दिल्ली-84 से प्रकाशित तथा मित्तल इण्टरप्राइजेज 2016 गोकुल शाह स्ट्रीट सीता राम बाजार दिल्ली-06 से मुद्रित।

***संपादकः प्रमोद तिवारी** *

लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित

नोटः पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है, तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय में ही किया जायेगा। राष्ट्र समाज पत्रिका में प्रकाशित सभी पद अवैतनिक हैं। पत्रिका के लिए भेजी गयी सामग्री के प्रकाशन पर पूर्व अनुबंध के बिना कोई भी पारिश्रमिक देने की व्यवस्था नहीं है।

08

युवा आंदोलन साझा नेतृत्व या बिखरती ताकत?
एक आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि भारतीय रेलवे प्रधानमंत्री सेल्फी...

12

जॉब नहीं तो सिंहासन हिलेगा
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ लिखा, 'जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा।'...

16

हैलो फ्रेंड से आईआईटी तक युवाओं में पैठ बचाने में कामयाब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी पार्टी के लिए संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए युवाओं की बीजेपी...

अंदर

20

‘हम अब टेक्नोलॉजी के नकलची नहीं, निर्माता बनेंगे’...
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कहलाने वाला भारत आज 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। ...

24

धंसती सड़कें और भ्रष्टाचार की गहरी नींव
जिस दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को आधुनिक भारत के तेज, सुरक्षित और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसकी सड़क उद्घाटन के महज ढाई महीने बाद पहली ही बरसात में धंस गई।...

50

हुमा कुरैशी ने जताई खुशी, फिल्म 'बयान' का आईएफएफएम में होगा ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर
अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने अपनी आगामी फिल्म 'बयान' के 2026 इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) में ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर को लेकर खुशी जाहिर की है।...

तिरंगा

भारतीय स्वाभिमान, एकता और अमर गौरव की गाथा

@ राष्ट्र समाज

राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश की आत्मा, स्वाभिमान और संप्रभुता का सबसे महान प्रतीक होता है। यह महज कपडे का एक टुकड़ा भर नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों की साझी चेतना, ऐतिहासिक संघर्षों, महान बलिदानों, समृद्ध संस्कृति और स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं की जीवंत अभिव्यक्ति है। जब गगन में ध्वज लहराता है, तो वह केवल एक प्रतीक नहीं फहराता, बल्कि विश्व पटल पर देश के गौरव, गरिमा और राष्ट्रीय अस्मिता की उद्घोषणा करता है। भारत में प्रतिवर्ष 22 जुलाई को 'राष्ट्रीय ध्वज दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसी ऐतिहासिक दिन, यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने 'तिरंगे' को स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया था। यह दिवस हमें स्वाधीनता संग्राम के उन अनगिनत जाने-अनजाने वीरों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर करके इस ध्वज की शान को कभी झुकने नहीं दिया।

हमारा तिरंगा विविधता में एकता की भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का संवाहक है। अनेक भाषाओं, धर्मों, जातियों और परंपराओं वाले इस महान देश में जब तिरंगा फहराता है, तो समस्त विभिन्नताएँ एक अटूट राष्ट्रीय पहचान में ढल जाती हैं। यह हमें बोध कराता है कि हमारी व्यक्तिगत और क्षेत्रीय अस्मिता से कहीं ऊपर 'राष्ट्र हित' और 'राष्ट्रीय पहचान' है। ध्वज की सार्थकता केवल स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित नहीं है। यह हर नागरिक के भीतर देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन का भाव जगाता है। चाहे स्कूल में प्रभातफेरी के दौरान होने वाला ध्वजारोहण हो, सीमाओं पर तैनात सैनिकों की ओजस्वी सलामी हो, वैश्विक खेल मंचों पर तिरंगा लहराते भारतीय एथलीट हों या अंतरिक्ष अभियानों में झंडा गाड़ते वैज्ञानिक–ये सभी दृश्य हमारे दिलों में राष्ट्रीय गर्व का संचार करते हैं।

राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वह केवल वर्तमान पीढ़ी का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राष्ट्रीय चेतना का आधार है। यदि किसी समाज में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान कम होने लगे, तो धीरे-धीरे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक विश्वास और सामूहिक उत्तरदायित्व भी कमजोर होने लगते हैं। राष्ट्र पहले भावनाओं से जुड़ता है, बाद में व्यवस्थाओं से। राष्ट्रीय ध्वज उन्हीं भावनाओं का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। दुर्भाग्य की बात है कि समय-समय पर कुछ सामाजिक और राजनीतिक तत्व अपने तात्कालिक स्वार्थों, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या वैचारिक कटुता के कारण राष्ट्रीय प्रतीकों को विवाद का विषय बना देते हैं। कभी राष्ट्रीय ध्वज को राजनीतिक मंचों पर अनावश्यक विवादों में घसीटा जाता है, कभी उसकी गरिमा को कम करने वाले वक्तव्य दिए जाते हैं और कभी उसे केवल दलगत दृष्टि से देखने का प्रयास किया जाता है। यह प्रवृत्ति अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक किसी दल, सरकार या विचारधारा के नहीं होते, वे पूरे राष्ट्र की साझा धरोहर होते हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, राजनीतिक दल आते-जाते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज सदैव राष्ट्र की स्थायी पहचान बना रहता है। जब राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग राजनीतिक लाभ या विरोध का माध्यम बन जाता है, तब सबसे अधिक क्षति राष्ट्र की सामूहिक चेतना को होती है।

लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना नागरिक का अधिकार है, नीतियों पर प्रश्न उठाना स्वस्थ परंपरा है, किंतु राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, संविधान और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों को विवाद का विषय बनाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। राजनीतिक मतभेद राष्ट्रभक्ति के स्थान पर नहीं आ सकते। राष्ट्र से ऊपर कोई दल, कोई नेता और कोई विचारधारा नहीं हो सकती। कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज पर आक्षेप वास्तव में उन लाखों बलिदानों का अनादर है, जिनके कारण यह ध्वज आज स्वतंत्र आकाश में लहरा रहा है।

भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष किसी दल के लिए नहीं, बल्कि इसी तिरंगे के सम्मान के लिए था। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना केवल संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि ऐतिहासिक उत्तरदायित्व भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान केवल औपचारिक अवसरों तक सीमित न रहे। यह हमारे व्यवहार, विचार और सार्वजनिक जीवन का स्थायी संस्कार बने। विद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास और उसके मूल्यों का समुचित अध्ययन कराया जाए। युवाओं को यह बताया जाए कि तिरंगा केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का स्मरण कराने वाला प्रेरक ध्वज है। सामाजिक संगठनों, सांस्कृतिक संस्थाओं और मीडिया को भी इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। आज डिजिटल युग में भी राष्ट्रीय ध्वज का महत्व और बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर उसकी गरिमा बनाए रखना, उसके उपयोग में संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना और राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीतिक प्रचार का साधन न बनने देना हम सभी का दायित्व है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा उसी जिम्मेदारी का सर्वोच्च स्वरूप है। राष्ट्रीय ध्वज हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा राष्ट्रप्रेम केवल नारों में नहीं, बल्कि आचरण में दिखाई देता है। ईमानदारी से अपना कार्य करना, कानून का पालन करना, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, करों का ईमानदारी से भुगतान करना, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहना और राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना-ये सभी तिरंगे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हैं। केवल ध्वज फहराना पर्याप्त नहीं, उसके आदर्शों को जीवन में उतारना अधिक आवश्यक है।

भारत आज विश्व मंच पर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, खेल, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां तिरंगे की प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर रही हैं। जब भारतीय वैज्ञानिक चंद्रमा पर सफलता का इतिहास रचते हैं, जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में तिरंगा लहराता है, जब सेना का जवान सीमा पर तिरंगे की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और आत्मगौरव का अमर प्रतीक है।

अंततः राष्ट्रीय ध्वज हमारी राष्ट्रीय आत्मा का दृश्य रूप है। वह हमें जोड़ता है, प्रेरित करता है और यह विश्वास दिलाता है कि मतभेदों के बावजूद हम एक हैं। उसकी गरिमा की रक्षा करना केवल सरकार का नहीं, प्रत्येक नागरिक का नैतिक और राष्ट्रीय दायित्व है। जिस दिन प्रत्येक भारतीय यह समझ लेगा कि तिरंगे का सम्मान वास्तव में अपने राष्ट्र, अपने इतिहास और अपने भविष्य का सम्मान है, उस दिन राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक चेतना की जड़ें और अधिक सुदृढ़ होंगी। तिरंगा हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है और हमारे अमर राष्ट्रीय स्वाभिमान का सर्वोच्च प्रतीक है। इसकी प्रतिष्ठा में ही भारत की प्रतिष्ठा निहित है।

युवा आंदोलन

साझा नेतृत्व या बिखरती ताकत?

@ डॉ. दीपक पाचपोर

देश के युवाओं, छात्रों एवं लोकतंत्र चाहने वाले हर किसी की उम्मीदें जगाने वाले कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केवल डेढ़ महीने के आंदोलन के जरिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा लेकर बेशक एक बड़ी जीत दर्ज की है। यह पहली बार है कि जब आंदोलन के जरिये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के किसी मंत्री को अपना पद छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ा है या यूं कहें कि सरकार को प्रधान से इस्तीफा देने के लिये कहा गया है। यह जीत निश्चित ही ठंडी हवा के झोंके की तरह है, लेकिन यह देखते हुए कि इस आंदोलन के कई स्टेकहोल्डर्स हैं, आश्चर्य नहीं होगा कि आगे चलकर इनमें श्रेय और नेतृत्व के लिए मारामारी होने लगे। यदि ऐसा हुआ तो इस आंदोलन के बिखरने में वक्त नहीं लगेगा। उससे केन्द्र और अनेक राज्य सरकारों को आंदोलनकारी युवाओं का दमन करने का मौका मिल जायेगा और अगले कई वर्षों तक शायद ही कोई आंदोलन सरकार के खिलाफ देखने को मिले।

इस या ऐसे आंदोलनों की निरंतरता जरूरी है ताकि सरकार को जनता की नाराजगी को तवज्जो देने और उसकी जायज मांगों के आगे झुकने की आदत पड़े। इसके पहले देश ने 2011 का लोकपाल आंदोलन देखा था। जनभावना का सम्मान करते हुए तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत की थी और तदनुसार आवश्यक संवैधानिक प्रावधान किये थे। यह अलग बात है कि उसके बाद आई नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने उन कानूनों को बेहद कमजोर कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने आंदोलनों के प्रति न सिर्फ उपेक्षा का बल्कि दमनात्मक का रवैया अपनाया। अनेक राज्यों में छोटी-बड़ी मांगों व समस्याओं को लेकर लोग-बाग बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन केंद्र अथवा संबंधित सरकारें या तो आंदोलनकारियों से वार्ता करती ही नहीं, करती भी हैं तो उनके पक्ष को मानती नहीं; और यदि नागरिक आंदोलन करें तो उनके खिलाफ शक्ति का प्रयोग करती हैं, उन्हें थानों व अदालतों की मुकदमेबाजी में फंसाती हैं, उनके घरों या कमाई के जरियों को बुलडोजरों से ध्वस्त करती है।

सरकार की इस तानाशाही व दमनपूर्ण व्यवहार के चलते ही लगभग 6 वर्ष पहले हुए किसान आंदोलन के बाद देश को बड़े आंदोलन देखने को नहीं मिले हैं। सड़कों के सूनेपन और संसद की आवारगी से निराश व अपने अधिकारों के प्रति सचेत नागरिकों, विशेषकर छात्रों तथा युवाओं को आशा की किरण अमेरिका में पढ़े अभिजीत दिपके में नजर आई जिसने डिजिटल स्वरूप का संगठन सीजेपी बनाया। यह संगठन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत द्वारा युवाओं-बेरोजगारों के लिए अशोभनीय शब्द कहने से आहत और मोदी के कार्यकाल में चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य नीट समेत अनेक परीक्षाओं के निरस्त होने से व्यथित लोगों ने सीजेपी के विचारों को इतना प्रचार-प्रसार दिया कि जंतर-मंतर पर लगभग डेढ़ माह तक बड़ा हुजूम आकर डटा रहा।

मई के पहले हफ्ते में आकर जब दिपके एवं उनके साथियों ने देश के युवाओं से जंतर-मंतर पर एकत्र होकर प्रदर्शन का आह्वान किया तो उन्हें और उनकी टीम को जैसा प्रतिसाद मिला, उससे जनता तो उत्साहित हुई सरकार के लिये वह स्तब्ध करने वाला जमावड़ा साबित हुआ। लेख-लद्दाख के पर्यावरणविद व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक भी इसमें न केवल शामिल हुए बल्कि उन्होंने लम्बी भूख हड़ताल भी की। सोनम वांगचुक को 20-21

दिनों की हड़ताल के बाद उनकी प्राण रक्षा के नाम पर पुलिस ने उन्हें पहले सफदरजंग तत्पश्चात मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। इससे 20 जुलाई को आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया जिसमें दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई। बड़ी संख्या में युवा, छात्र तथा अन्य लोग घायल हुए। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया उससे एक ओर तो देश भर के छात्र-युवा उग्र हो उठे, तो वहीं दुनिया भर में इसके वीडियो, चित्र आदि वायरल हुए। इतना ही नहीं, कई देशों के शहरों में भारतीयों ने प्रदर्शन कर भाजपा सरकार की आलोचना की।

बढ़ते जनदबाव के चलते सरकार ने न सिर्फ प्रधान को मंत्रिमंडल से चलता किया वरन शनिवार व रविवार की आधी रातों को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश दिये जो मूलतः युवाओं व छात्रों को संबोधित थे। इसमें उन्होंने परीक्षाएं लीक करने को 'घोर पाप' बतलाते हुए जानकारी दी कि परीक्षाएं लीक होने के खिलाफ कड़े प्रावधान किये जा रहे हैं व शिक्षा व्यवस्था सुधारी जायेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सोनम की भूख हड़ताल तुड़वाई और दूसरे, सीजेपी के नेताओं से समझौता किया जिसके बाद जंतर-मंतर के धरने को समेटने का ऐलान हो गया। संगठन के प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि सरकार ने वादा किया है कि धरना-प्रदर्शन को लेकर जिन लोगों के खिलाफ दर्ज मामले हटा दिये जायेंगे; नये प्रकरण भी दर्ज नहीं होंगे। हालांकि कई स्थानों पर इसके बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाइयां जारी रहीं जिसके चलते सीजेपी ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा हुआ तो कॉक्रोच दोबारा जंतर-मंतर पर जुटेंगे। उन्होंने सरकार से कहा कि वादे के अनुसार वह सभी राज्यों की पुलिस को मंगलवार तक इस आशय का आदेश जारी करे।

इस आदेश का सबसे बड़ा उल्लंघन बिहार में होता दिखा जहां रविवार व सोमवार को पुलिस ने आंदोलनकारियों को उनके घरों से उठाना शुरू किया। इससे नाराज 'आंदोलन की उपलब्धि' कही जाने वाली ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष (दिल्ली विवि से निकलीं तथा वर्तमान में जेएनयू में शोधार्थी) नेहा बोरा ने बिहार सरकार को धमकी दी कि यदि कार्रवाइयां जारी रहीं तो युवा व छात्र बिहार बंद कराएंगे। नेहा ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर तत्काल प्रभाव का आदेश जारी कराया कि बिहार में कोई कार्रवाई न की जाये और नये मामले दर्ज न हों। अब नेहा देश की युवा-छात्र शक्ति का बड़ा चेहरा है जिनकी एक बड़ी फॉलोइंग है- डिजिटल और जमीनी दोनों स्तरों पर। वे इस अभियान की एक शक्ति केन्द्र बनी रहेंगी।

हालांकि इस आंदोलन के प्रमुख नेता अभिजीत दिपके एवं उनके कुछ प्रमुख सिपहसालारों को माना जाता है जो सीजेपी

बनाने में परस्पर सहयोगी थे। जब तक दिपके भारत (दिल्ली) नहीं आये थे, बाकियों ने अभियान की कमान सम्हाली थी। वांगचुक के शामिल होने से माना गया कि वे भी एक प्रमुख नेता हैं जो आंदोलन को आगे बढ़ायेंगे। अस्पताल में आधी रात को सरकार के मंत्रियों के हाथों जूस पीकर अपनी भूख हड़ताल तोड़ने से उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। हालांकि पहले से ही उनके तथा उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो को भाजपा की समर्थक बताया जाता रहा है।

इस मसले में कांग्रेस भी एक बड़ी स्टेकहोल्डर है। वह पहले से इस मुद्दे को कई राज्यों में उठा रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मुद्दे को संसद के भीतर-बाहर उठाया। मीडिया के समक्ष पैलेट गन से घायल व्यक्ति को तत्पश्चात इन युवा व छात्र नेताओं को लाया। वे प्रदर्शन स्थल पर संविधान को लेकर अपने विचारों से सबको प्रभावित करने वाले मोहम्मद इरफान से उनकी झोपड़ी में जाकर भी मिले। साफ है कि इस पूरे मुद्दे को जो भी भावी स्वरूप दिया जायेगा, उसमें कांग्रेस को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकेगा। इस मामले में सफलता हासिल करने के लिये सभी शक्ति केन्द्रों को संयुक्त लड़ाई लड़नी होगी। अपने वैचारिक आग्रहों को कुछ समय के लिये किनारे रखना होगा- सभी को।

उदाहरण पेश करता है झारखंड का छात्र आंदोलन

हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित जंतर-मंतर का आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर ठएएळ पेपर लीक, पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों को मुआवजा, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में सुधार, प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की मांग को लेकर शुरू हुआ। लेकिन उस आंदोलन में प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली, देश की सेना को अपशब्द, सीआरपीएफ एवं पुलिस के जवानों के साथ दुर्व्यवहार, मीडिया के साथ अभद्रता, पत्थरबाजी, अपराधियों और टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ ने न सिर्फ देश अपितु विदेशों में भी भारत का सर शर्म से झुका दिया, जिस युवाओं और जेन-जीमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव देश का भविष्य बताते रहे हैं, उनका अचार झ विचार बिल्कुल शर्मिंदा करने वाला था, हालांकि आंदोलन के कई सप्ताह तक चलने के बाद अंततः केंद्र सरकार तथा आंदोलनकारियों के बीच वार्ता हुई। इसके बाद सरकार ने सभी मांगों को मान लिया । जंतर-मंतर के उस आंदोलन के बाद एक और छात्र आंदोलन चर्चा के केंद्र में है। झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों केवल एक धरना स्थल नहीं, बल्कि लाखों प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदों का प्रतीक बन गया है। जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ यह अनिश्चितकालीन आंदोलन देखते-ही-देखते पूरे राज्य के युवाओं की आवाज बन गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार हो रही देरी, रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति नहीं होने और पारदर्शिता की मांग को लेकर हजारों छात्र रांची पहुंचे और अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आरंभ किया। शुरूआत में यह आंदोलन कुछ छात्र संगठनों और प्रतियोगी अभ्यर्थियों तक सीमित था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी गूंज पूरे झारखंड में फैल गई। देखते ही देखते राज्य के लगभग सभी जिलों से छात्र इसमें शामिल होने लगे। खास बात यह रही कि आंदोलन के दौरान छात्रों ने स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष किसी सरकार या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसी भर्ती व्यवस्था के पक्ष में है, जिस पर युवाओं का भरोसा कायम रह सके। उनकी प्रमुख मांगों में झारखंड लोक सेवा आयोग (खढरड) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (खररड) की भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, समयबद्ध भर्ती कैलेंडर और रिक्त सरकारी पदों पर शीघ्र नियुक्ति शामिल रही। जैसे-जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, उसका स्वर और व्यापक होता गया। छात्र नेताओं ने भूख हड़ताल शुरू की, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षकों और अभिभावकों ने समर्थन दिया तथा देश के अन्य राज्यों के प्रतियोगी छात्रों ने भी एकजुटता व्यक्त की। आंदोलनकारियों ने यह भी घोषणा की कि यदि उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे तिरंगा मार्च निकालेंगे और विधानसभा का शांतिपूर्ण घेराव करेंगे। इस घटनाक्रम ने झारखंड छात्र आंदोलन को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। वास्तव में यह आंदोलन किसी एक परीक्षा या एक आयोग तक सीमित नहीं है। यह उन लाखों युवाओं की पीड़ा का प्रतीक है जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं की अनिश्चितता के कारण उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा समाप्त होने की स्थिति में पहुँच गई है, अनेक परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और युवाओं का व्यवस्था पर विश्वास लगातार कमजोर हुआ है। ऐसे में झारखंड का छात्र आंदोलन केवल विरोध का आंदोलन नहीं, बल्कि व्यवस्था में विश्वास बहाल करने का आंदोलन बन गया है। भारतीय लोकतंत्र में छात्र आंदोलनों का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है।

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में ठीक यही बात दोहराई। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक ने युवाओं का आज छीन लिया, रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल छीन लिया और दिल्ली में सिर्फ इसलिए लाठियां चलीं क्योंकि उन्होंने अपने हक की बात कही। अब बहाने नहीं चलेंगे। जवाबदेही लीजिए या कुर्सी छोड़िए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। पार्टी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे।

जॉब नहीं तो सिंहासन हिलेगा

@ अजय कुमार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ लिखा, 'जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा।' यह पोस्ट ठीक उसी समय आया जब देश भर में बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं का गुस्सा अभी भी थमा नहीं है। कोटा और देहरादून के बाद अब यह अभियान 'छात्रों की गूंज' 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी कॉलेज मैदान में उतरने जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि मिस्ड कॉल और क्यूआर कोड के जरिए डेढ़ लाख से ज्यादा छात्रों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संकेत है। प्रयागराज कभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मक्का माना जाता था। यहां हर साल देश-प्रदेश से लाखों युवा आते हैं। फॉर्म भरते हैं, फीस जमा करते हैं, सालों साल कोचिंग करते हैं और फिर इंतजार करते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियां और परीक्षा पैटर्न में बदलाव ने इन युवाओं का भरोसा तोड़ दिया। नीट यूजी

2026 परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक के बाद पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। मई में करीब 22 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। लीक की खबर आने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर जून में दोबारा परीक्षा हुई जिसमें करीब 20 लाख छात्र शामिल हुए। दो लाख के आसपास छात्र दोबारा नहीं बैठे। यह आंकड़ा बताता है कि कितने युवाओं का एक साल बर्बाद हो गया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए प्रदर्शन ने इस गुस्से को नया रूप दिया। जुलाई में जब हजारों छात्र संसद की ओर बढ़े तो पुलिस ने लाठियां चलाईं और पैलेट गन का इस्तेमाल भी हुआ। कई युवा घायल हुए। कुछ दिनों बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही। लेकिन युवाओं का सवाल अभी भी वही है कि सिस्टम क्यों बार-बार नाकाम साबित होता है।

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में ठीक यही बात दोहराई। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक ने युवाओं का आज छीन लिया, रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल छीन लिया और दिल्ली में सिर्फ इसलिए लाठियां चलीं क्योंकि उन्होंने अपने हक की बात कही। अब बहाने नहीं चलेंगे। जवाबदेही लीजिए या कुर्सी छोड़िए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। पार्टी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। केपी ग्राउंड पर मंच तैयार हो रहा है। आसपास के जिलों से छात्रों को लाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कौशांबी, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, भदोही, मिजार्पुर, वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों से युवा आने वाले हैं। भदोही से अकेले हजारों छात्रों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को एक मंच देने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में युवा और बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की डबल इंजन सरकार रोजगार देने के दावे करती रही है। लेकिन पेपर लीक के मामले और भर्तियों में देरी ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रयागराज में तैयारी करने वाले छात्रों में ब्राह्मण, भूमिहार, मौर्य, कुर्मी और दलित समुदाय के युवा बड़ी संख्या में हैं। इनमें से कई पारंपरिक रूप से भाजपा के साथ रहे हैं। लेकिन अगर ये युवा बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था की अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की ओर झुकते हैं तो 2027 के समीकरण बदल सकते हैं।इतिहास गवाह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति ने देश को कई नेता दिए। चंद्रशेखर आजाद की शहादत की भूमि से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, वीपी सिंह व हेमवती नंदन बहुगुणा तक की राजनीतिक यात्रा यहीं से शुरू हुई। छात्र आंदोलन हमेशा सत्ता के खिलाफ जनमत बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता आया है।

राहुल गांधी का यह दौरा उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश लगता है।कोटा में 17 जून को अभियान शुरू हुआ था। देहरादून में 17 जुलाई को दूसरा चरण हुआ। अब प्रयागराज तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण है। पहले दिल्ली में 9 अगस्त को बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन अनुमति न मिलने के बाद इसे प्रयागराज शिफ्ट कर दिया गया। कांग्रेस की रणनीति साफ है। 2027 के चुनाव को जातिगत समीकरणों के बजाय युवा और बेरोजगारी के नैरेटिव पर केंद्रित करना। सपा के पीडीए फॉमूर्ले के साथ अगर कांग्रेस छात्र शक्ति को जोड़ लेती है तो गठबंधन का आधार और मजबूत हो सकता है। झारखंड में जेपीएससी को लेकर भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर का असर कई राज्यों में दिख रहा है। ऐसे में प्रयागराज का कार्यक्रम सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संदेश बन सकता है। डेढ़ लाख पंजीकरण का दावा अगर मैदान में भीड़ में तब्दील होता है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। प्रशासनिक अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था और मौसम सब कुछ देखना होगा। पार्टी के अंदर भी तैयारियों को लेकर कुछ घर्षण की खबरें आई हैं। फिर भी अजय राय और स्थानीय नेता दावा कर रहे हैं कि केपी ग्राउंड से लेकर शहर की गलियां युवाओं से भर जाएंगी।राहुल गांधी के पोस्ट का स्वर आक्रामक है। सिंहासन हिलने की बात सिर्फ नारा नहीं, बल्कि युवाओं के गुस्से को राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश है। पेपर लीक के बाद शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, भर्तियों में देरी और दिल्ली की घटना ने एक नई पीढ़ी को सड़क पर उतार दिया। अब देखना यह है कि 8 अगस्त को प्रयागराज में यह गूंज कितनी दूर तक जाती है। अगर युवा सच में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तो 2027 के यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के मिशन का आगाज यहीं से हो सकता है। प्रयागराज की धरती ने हमेशा राजनीति को नई दिशा दी है। इस बार भी वही इतिहास दोहराया जा सकता है।

संघ प्रमुख का यह कहना कि वे 'नई पीढ़ी पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं,' एक बहुत बड़ा वक्तव्य है । यह भरोसा इस समझ से उपजा है कि आज का युवा पाखंड को पसंद नहीं करता। वह जो सोचता है, वही बोलता है; उसकी कथनी और करनी में दिखावा नहीं होता। उनकी देशभक्ति किसी प्रदर्शनकारी राष्ट्रवाद का हिस्सा नहीं है, बल्कि देश को आंतरिक रूप से मजबूत और अधिक न्यायसंगत बनाने की उनकी स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित है।

बदलता संघ और बदलता युवा

@ अशोक भाटिया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परंपरा, अनुशासन और प्राचीन मूल्यों को सर्वोपरि रखने के लिए जाना जाता है। ऐसे में जब संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत समकालीन युवा पीढ़ी–जिन्हें 'जेन-जी' और 'जेन-अल्फा' कहा जाता है–के पक्ष में खुलकर खड़े होते हैं, तो यह भारतीय विमर्श में एक युगांतरकारी मोड़ का संकेत है। हाल ही में संघ प्रमुख ने जिस बेबाकी और संवेदनशीलता के साथ युवाओं की सोच, उनके अधिकारों, उनके विरोध प्रदर्शनों और उनकी देशभक्ति का समर्थन किया है, उसने देश के नीति-निमार्ताओं व पुरानी पीढ़ी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। यह संदेश दशार्ता है कि संघ समय के साथ न केवल बदल रहा है, बल्कि नए भारत की नई सोच को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। डिजिटल बदलावों और बदलते सामाजिक परिवेश के बीच यह संदेश राष्ट्र निर्माण की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

अमूमन हर दौर में पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से शिकायतें रही हैं। आज भी अक्सर 'जेन-जी' को लेकर यह धारणा बनाई जाती है कि वे रील्स और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में खोए हुए हैं, वे एकाग्रता की कमी से जूझ रहे हैं और अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। लेकिन डॉ. मोहन भागवत ने इन तमाम रूढ़िवादिता को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज की युवा पीढ़ी पिछली पीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक ईमानदार, पारदर्शी, जागरूक और देशभक्त है।

संघ प्रमुख का यह कहना कि वे 'नई पीढ़ी पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं,' एक बहुत बड़ा वक्तव्य है। यह भरोसा इस समझ से उपजा है कि आज का युवा पाखंड को पसंद नहीं करता। वह जो सोचता है, वही बोलता है; उसकी कथनी और करनी में दिखावा नहीं होता। उनकी देशभक्ति किसी प्रदर्शनकारी राष्ट्रवाद का हिस्सा नहीं है, बल्कि देश को आंतरिक रूप से मजबूत और अधिक न्याय संगत बनाने की उनकी स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित है। जब देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन युवाओं की इस प्रामाणिकता को मान्यता देता है, तो यह युवाओं के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान देता है और पुरानी पीढ़ी के संशय को दूर करता है।

इस संदेश का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा में रहने वाला हिस्सा वह था, जहां डॉ. भागवत ने युवाओं के विरोध प्रदर्शनों और उनके अधिकारों की बात की। पिछले कुछ वर्षों में देश ने विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों पर छात्रों के उग्र आंदोलन देखे हैं। दुर्भाग्यवश, कई बार ऐसे आंदोलनों को फौरन दबाने या उन्हें 'देश-विरोधी' या 'गुमराह' बताने की कोशिशें की जाती रही हैं। लेकिन सरसंघचालक ने इस पर बेहद परिपक्व और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण रखा।

उन्होंने साफ किया कि व्यवस्था, सरकारी नीतियों या किसी घटना के खिलाफ आवाज उठाना और विरोध प्रदर्शन करना युवाओं का लोकतांत्रिक अधिकार है। युवाओं का गुस्सा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुधारने, पारदर्शी बनाने और अधिक जवाबदेह देखने के लिए होता है। किसी

आंदोलन में शामिल होने मात्र से कोई युवा देश-विरोधी नहीं हो जाता । यह बयान उन ताकतों के लिए एक कड़ा सबक है जो हर असहमति की आवाज को दबा देना चाहती हैं। लोकतंत्र की असली ताकत निरंतर संवाद में है, दमन में नहीं, और युवाओं का विरोध इसी स्वस्थ संवाद की मांग करता है।

आज का युवा सूचना क्रांति के उस दौर में जी रहा है जहां दुनिया भर का ज्ञान उसकी उंगलियों पर है। वह किसी भी बात या परंपरा को सिर्फ इसलिए चुपचाप नहीं मान लेता क्योंकि वह किसी बुजुर्ग या प्राचीन व्यवस्था ने कही है। वह तर्क चाहता है, वह प्रमाण चाहता है, वह न्यायसंगत कारण चाहता है। डॉ.मोहन भागवत ने युवाओं के इस खोजी स्वभाव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की खुलकर सराहना की है। उन्होंने माना कि आज की पीढ़ी बिना डरे सीधे सवाल पूछता है व पुरानी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वे इन सवालों से भागने या नाराज होने के बजाय उनके तार्किक व संतोषजनक जवाब दें।

यह दृष्टिकोण संघ की पारंपरिक छवि से अलग और प्रगतिशील है। संघ प्रमुख का यह मानना कि समस्याओं या असंतोष का समाधान 'बल' या 'उपेक्षा' से नहीं हो सकता, आज के समय की सबसे बड़ी नीतिगत जरूरत है। जब छात्र किसी नीति पर अपनी चिंताएं जताते हैं, तो प्रशासन या समाज को उनके साथ एक 'मेंटर' की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि किसी क्रूर शासक की तरह। उनके तर्कों को संवेदनशीलता से सुनना व उनकी आशंकाओं को दूर करना ही उनके असंतोष को शांत करने का एकमात्र सर्वमान्य उपाय है।

आज का भारतीय समाज वैचारिक रूप से अत्यधिक ध्रुवीकृत है। दक्षिणपंथ और वामपंथ के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि मध्यमार्ग गायब सा दिखता है। ऐसे माहौल में संघ प्रमुख का यह बयान एक पुल का काम करता है। यह संदेश उन युवाओं तक भी एक सकारात्मक प्रतिध्वनि के रूप में पहुंचता है जो संघ को हमेशा एक अत्यंत पुरातनपंथी संस्था के रूप में देखते आए हैं। जब वे देखते हैं कि संघ का सर्वोच्च नेता उनके विरोध करने के अधिकार और उनकी तार्किकता का सम्मान कर रहा है, तो वैचारिक कट्टरता की दीवारें कमजोर होती हैं ।

यह लेख इस बुनियादी सत्य को रेखांकित करता है कि राष्ट्र निर्माण किसी एक विचारधारा के एकाधिकार से नहीं हो सकता। इसके लिए देश के हर युवा की ऊर्जा, उसकी स्वतंत्र सोच और उसके रचनात्मक विरोध की आवश्यकता है। संघ प्रमुख ने युवाओं को यह अहसास कराया है कि वे देश के भविष्य ही नहीं, बल्कि वर्तमान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं और राष्ट्र को उनके सहयोग की जरूरत है।

डॉ. भागवत का यह वक्तव्य जितना युवाओं के लिए मार्गदर्शक है, उससे कहीं अधिक यह देश की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस तंत्र और राजनीतिक दलों के लिए एक गंभीर 'चेतावनी' की तरह है । पिछले कुछ समय में देश के अलग-अलग हिस्सों में छात्रों की मांगों को जिस तरह बलपूर्वक दबाया गया, संघ प्रमुख का यह बयान उन प्रशासनिक नीतियों पर एक परोक्ष प्रहार है।

यदि प्रशासनिक तंत्र युवाओं को केवल एक 'कानून-व्यवस्था' की समस्या के रूप में देखता रहेगा, तो हम अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का कभी लाभ नहीं उठा पाएंगे। विश्वविद्यालयों को पुलिस छावनी बनाने के बजाय उन्हें स्वतंत्र विचार-विमर्श का केंद्र बनाना होगा। जब तक युवाओं को यह विश्वास नहीं होगा कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जा रहा है, तब तक सड़कों का असंतोष पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। प्रशासन को अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़कर युवाओं के साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा।

डॉ. मोहन भागवत का यह संदेश केवल 'जेन-जी' के लिए प्रेरणा नहीं है, बल्कि पुरानी पीढ़ी, राजनीतिक दलों और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक 'वेक-अप कॉल' है। हमें युवाओं को एक समस्या के रूप में देखना बंद करना होगा; वे वास्तव में देश की समस्याओं का सबसे आधुनिक समाधान हैं। युवा आबादी की ऊर्जा को दबाने के बजाय उसे सही दिशा देना ही समझदारी है।

यदि भारत को सचमुच एक वैश्विक शक्ति, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और 'विश्वगुरु' बनना है, तो हमें अपनी युवा आबादी की इस ऊर्जा, उनकी बेबाकी और उनकी तार्किकता को सहेजना होगा। संघ प्रमुख ने इस दिशा में संवाद का हाथ बढ़ाकर एक बड़ी पहल की है। अब वास्तविक जिम्मेदारी सरकार, शिक्षण संस्थानों और परिवारों की है कि वे युवाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। 'जेन-जी' पर किया गया यह भरोसा ही आने वाले कल के समृद्ध, सशक्त, समावेशी और लोकतांत्रिक भारत की नींव बनेगा ।

नीट पेपर लीक के मामले में उठाए गए सख्त कदमों और नीतिगत सुधारों ने यह दिखा दिया कि सरकार केवल आश्वासन देने में नहीं, बल्कि ठोस परिणाम देने में विश्वास रखती है। नतीजतन, विपक्ष के पास अब सरकार की आलोचना करने के लिए वह धारदार हथियार नहीं बचा, जो शुरूआती दिनों में नजर आ रहा था।

हैलो फ्रेंड से आईआईटी तक

युवाओं में पैठ बचाने में कामयाब रही सरकार

@ संजय सक्सेना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी पार्टी के लिए संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए युवाओं की बीजेपी और उनकी सरकार के प्रति नाराजगी के संकट को अपनी वाकपटुता से काफी हद तक टाल दिया है। विपक्ष युवाओं की पीठ पर चढ़कर मोदी सरकार को घेरने का जो सपना पाले हुए था, वह लगभग टूट चुका है। हाल ही में नीट पेपर लीक के बाद देश की राजनीति में युवाओं की भूमिका, उनकी मोदी सरकार से नाराजगी और उससे निपटने के लिए सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच चली आ रही रणनीतिक खींचतान ने एक नया मोड़ ले लिया है। नीट पेपर लीक जैसी गंभीर घटनाओं के बाद उपजे असंतोष को जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में भुनाने और थामने के प्रयास किए गए, वे भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य को गहराई से समझने का अवसर देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरूआत तब हुई, जब काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने देश के युवाओं को साथ लेकर जंतर-मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। हालांकि, यह प्रदर्शन कुछ विवादों के घेरे में भी रहा, लेकिन इसके बावजूद इसे काफी सफल माना गया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि सीजेपी ने मोदी सरकार के सामने जो मांगें रखी थीं, उन्हें अंततः देर से ही सही, लेकिन सरकार को पूरा करना ही पड़ा। इस सफलता ने अचानक से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में युवाओं को ला खड़ा किया, और यहीं से राजनीतिक विश्लेषकों तथा पंडितों के बीच एक नए नैरेटिव की शुरूआत हुई।

राजनीतिक पंडितों और जानकारों ने यह नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया कि आज की जेन जी यानी देश का युवा वर्ग मोदी सरकार से बुरी तरह नाराज चल रहा है। इस वर्ग का मोहभंग होना किसी भी सत्ताधारी दल के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता था। इस बात का अहसास होते ही विपक्षी दलों ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता तुरंत मैदान में उतर आए और युवाओं को सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाने के लिए प्रेरित करने लगे। विपक्षी नेताओं ने इस दौरान पैलेट गन और एके-47 जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों का हवाला देते हुए युवाओं की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया, ताकि सरकार के खिलाफ एक बड़ा जनआंदोलन खड़ा किया जा सके। विपक्ष को यह लगने लगा था कि युवाओं की यह नाराजगी आगामी चुनावों में उनके लिए संजीवनी का काम करेगी और बीजेपी के किले को भेदने में मददगार साबित होगी।

लेकिन, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पूरे घटनाक्रम की नब्ज को तुरंत पहचान लिया और डैमेज कंट्रोल में एक पल की भी देरी नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और सबसे पहले एक अनूठे अंदाज में वीडियो जारी कर देश के युवाओं को 'हैलो फ्रेंड' कहकर संबोधित किया। इस

आधुनिक और युवा-अनुकूल संवाद शैली ने तुरंत ही सोशल मीडिया और युवाओं के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजा। इसके बाद प्रधानमंत्री के चार और वीडियो सिलसिलेवार तरीके से सामने आए, जिनमें उनकी संवेदनशीलता और युवाओं के प्रति चिंता साफ झलकी। पेपर लीक जैसी समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान निकालने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन सहित उन्होंने कई कड़े और निर्णायक फैसले लिए। सिर्फ वर्चुअल माध्यमों तक ही सीमित न रहते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आईआईटी दिल्ली का दौरा किया और सीधे तौर पर वहां के युवाओं से संवाद स्थापित किया। उन्होंने युवाओं की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व को बख्शेगी नहीं।

कुल मिलाकर, सरकार की इस त्वरित और बहुआयामी रणनीति ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी ने युवाओं की नाराजगी से होने वाले संभावित राजनीतिक नुकसान को समय रहते सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया है। इस डैमेज कंट्रोल अभियान में केवल सरकार ही सक्रिय नहीं रही, बल्कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस व उसके प्रमुख मोहन भागवत भी पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद पड़े।

आरएसएस प्रमुख की सक्रियता व वैचारिक स्तर पर युवाओं से जुड़ने के प्रयासों ने इस अभियान को एक मजबूत वैचारिक संबल प्रदान किया। संघ के अनुषांगिक संगठनों ने भी परिसरों व युवाओं के बीच जाकर संवाद स्थापित किया, जिससे विपक्ष द्वारा गढ़ा गया नैरेटिव धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा, जिसमें युवाओं को सरकार के खिलाफ पूरी तरह खड़ा हुआ दिखाया जा रहा था।

दूसरी ओर, इस पूरी कवायद के बाद विपक्ष पूरी तरह से खाली हाथ खड़ा नजर आने लगा है। जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की योजना बना रहा था, सरकार ने उन पर त्वरित कार्रवाई करके विपक्ष के हाथ से एजेंडा ही छीन लिया। नीट पेपर लीक के मामले में उठाए गए सख्त कदमों और नीतिगत सुधारों ने यह दिखा दिया कि सरकार केवल आश्वासन देने में नहीं, बल्कि ठोस परिणाम देने में विश्वास रखती है। नतीजतन, विपक्ष के पास अब सरकार की आलोचना करने के लिए वह धारदार हथियार नहीं बचा, जो शुरूआती दिनों में नजर आ रहा था। कुल मिलाकर, इस राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आधुनिक राजनीति में जनता की नब्ज पहचानना और समय पर उचित कदम उठाना कितना जरूरी है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने अपनी संवाद कुशलता और निर्णायक क्षमता का परिचय देकर स्थिति को संभाल लिया, वहीं विपक्ष एक बार फिर रणनीतिक रूप से पिछड़ता हुआ दिखाई दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केवल विरोध की राजनीति करने से बड़े राजनीतिक बदलाव हासिल नहीं किए जा सकते।

भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है और बिजली का बड़ा हिस्सा कोयले से बनता है। 1 यूनिट बिजली बचाने का मतलब है 1.5 किलो कोयला बचाना और 0.8 किलो सीओ2 कम करना। अगर दिल्ली-एनसीआर का हर घर महीने में सिर्फ 50 यूनिट बिजली बचाए, तो महीने में 5 करोड़ यूनिट बचेंगे।

‘बिजली बचाएं देश बचाएं’

@ प्रमोद तिवारी

‘घर से लेकर दफ्तर तक के 50 आसान टिप्स’

‘भूमिकाः क्यों जरूरी है बिजली बचाना?’

देश के केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार ‘ऊर्जा संरक्षण’ पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है और बिजली का बड़ा हिस्सा कोयले से बनता है। 1 यूनिट बिजली बचाने का मतलब है 1.5 किलो कोयला बचाना और 0.8 किलो सीओ2 कम करना। अगर दिल्ली-एनसीआर का हर घर महीने में सिर्फ 50 यूनिट बिजली बचाए, तो महीने में 5 करोड़ यूनिट बचेंगे। इससे 3 बड़े पावर प्लांट बंद किए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं आसान 50 टिप्सः

‘भाग 1ः घर के कमरे में बिजली बचत - 20 टिप्स’

‘लाइट और पंखे’

1. **‘एलईडी लगाएं’**: 1 सीएफएल की जगह एलईडी लगाएं। 20डब्ल्यू एलईडी = 100ह बल्ब जितनी रोशनी। साल में ₹1000 बचत
2. **‘जरूरत पर ही लाइट’**: कमरे से निकलते समय लाइट-पंखा बंद करने की आदत डालें। महीने में 40 यूनिट बचेंगे
3. **‘सीलिंग फैन साफ रखें’**: धूल वाले पंखे 15% ज्यादा बिजली खाते हैं। हर महीने पंखा पोंछें
4. **‘फैन की स्पीड’**: एसी के साथ फैन मीडियम स्पीड पर चलाएं। ठंडक ज्यादा और बिजली कम
5. **‘ट्यूबलाइट की जगह एलईडी ट्यूब’**: पुरानी ट्यूबलाइट 40डब्ल्यू लेती है, एलईडी ट्यूब 18डब्ल्यू में काम करती है

'एसी से जुड़े टिप्स'

6.**'24 डिग्री का नियम'**: एसी को 24-25°सी पर चलाएं। हर 1 डिग्री कम करने पर 6% बिजली ज्यादा लगती है

7. **'एसी+ फैन कॉम्बो'**: एसी 26 पर + सीलिंग फैन चलाएं। 3°सी ज्यादा ठंडक बिना एक्स्ट्रा बिजली

8. **'एसीकी सर्विस'**: हर 6 महीने में अउ सर्विस कराएं। गंदे फिल्टर से 15% ज्यादा बिजली लगती है

9. **'कमरा सील करें'**: एसी वाले कमरे के दरवाजे-खिड़की बंद रखें। लीकेज से बिजली बर्बाद होती है

10.**'धूप रोकें'**: दिन में पर्दे लगाएं। कमरा ठंडा रहेगा तो एसी कम चलेगा

'टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल'

11.**'स्टैंडबाय बंद करें'**: टीवी, सेट-टॉप बॉक्स बंद करके भी 10डब्ल्यू लेते हैं। स्विच से बंद करें। साल में ₹600 बचत

12.**'लैपटॉप चार्जिंग'**: 100% चार्ज होते ही प्लग निकालें। ओवरचार्जिंग से बैटरी और बिजली दोनों खराब

13.**'5 स्टार रेटिंग'**: नया फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन लेते समय 5 स्टार बीईई रेटिंग वाला ही लें

14. **'स्क्रीन ब्राइटनेस कम'**: मोबाइल-लैपटॉप की ब्राइटनेस 50% रखें। बैटरी और बिजली दोनों बचेगी

'भाग 2: किचन और फ्रिज - 10 टिप्स'

15.**'फ्रिज का तापमान'**: फ्रिज 3-4°सी और फ्रीजर -18°सी पर रखें। बहुत ठंडा रखने से बिजली बर्बाद

16.**'गर्म खाना न रखें'**: खाना ठंडा कर-के ही फ्रिज में रखें। गर्म बर्तन रखने से कंप्रेसर ज्यादा चलता है

17.**'फ्रिज में जगह'**: फ्रिज को दीवार से 15 सीएम दूर रखें। हवा पास होगी तो कंप्रेसर कम चलेगा

18.**'प्रेशर कुकर'**: दाल-चावल प्रेशर कुकर में बनाएं। 70% गैस और 50% समय बचता है

19.**'इंडक्शन/माइक्रोवेव'**: छोटे काम के लिए गैस की जगह इंडक्शन यूज करें। 30% तेज और बिजली कम

20.**'ओवन प्रीहीट न करें'**: केक को छोड़कर बाकी चीजों में ओवन प्रीहीट की जरूरत नहीं

21.**'केतली'**: पूरा पानी उबालें जितना जरूरत हो। आधा कप के लिए पूरी केतली न चलाएं

22.**'फ्रिज का रबर चेक करें'**: दरवाजे का रबर लीक कर रहा हो तो ठंडी हवा निकलती है और बिल बढ़ता है

'भाग 3: वॉशिंग मशीन,गीजर,मोटर-10 टिप्स'

23. **'पूरी लोड में कपड़े धोएं'**: वॉशिंग मशीन आधी भरी चलाने से प्रति कपड़ा बिजली डबल लगती है

24.**'ठंडे पानी से कपड़े'**: डिटर्जेंट आजकल ठंडे पानी में भी काम करते हैं। गीजर मत चलाएं

25.**'गीजर टाइमर'**: गीजर में टाइमर लगवाएं। 20 मिनट में पानी गर्म, फिर ऑटो बंद

26.**'सोलर गीजर'**: सरकारी सब्सिडी पर सोलर गीजर लगवाएं। 2 साल में पैसा वसूल

27.**'पानी की मोटर'**: बोरवेल मोटर सुबह-शाम ठंडे समय चलाएं। वोल्टेज सही रहेगा और बिजली कम लगेगी

28.**'टंकी में बॉल वाल्व'**: ओवरफ्लो रोकने के लिए बॉल वाल्व लगवाएं। मोटर बार-बार नहीं चलेगी

29.**'इन्वर्टर बैटरी'**: इंवर्टर को पूरी डिस्चार्ज करके ही चार्ज करें। बैटरी लाइफ और बिजली दोनों बचेगी

'भाग 4: ऑफिस, दुकान और फैक्ट्री - 10 टिप्स'

30.**'डेलाइट यूज करें'**: दिन में खिड़की से आने वाली रोशनी यूज करें। लाइट बंद रखें

31.**'सेंसर लाइट'**: टॉयलेट, सीढ़ी में मोशन सेंसर लाइट लगाएं। कोई नहीं तो लाइट बंद

32.**'कंप्यूटर स्लीप मोड'**: 15 मिनट न यूज हो तो कंप्यूटर स्लीप पर चला जाए, सेटिंग करें

33.**'प्रिंटर-फोटोकोपी'**: काम खत्म होते ही मेन स्विच बंद करें

34.**'एसी मेंटेनेंस'**: ऑफिस का सेंट्रल एसी हर 3 महीने में सर्विस हो

35.**'सोलर पैनल'**: छत पर सोलर लगवाएं। पीएम सूर्य घर योजना में 40% सब्सिडी मिलती है

36.**'पावर फैक्टर'**: फैक्ट्री में एपीएफसी पैनल लगवाएं। बिजली बिल 10% तक कम होगा

37.**'ऊर्जा ऑडिट'**: साल में 1 बार ऊर्जा ऑडिट कराएं। बीईई से फ्री ऑडिट भी होता है

'भाग 5:सरकारी योजनाएं व बड़े फायदे'

'सरकार क्या कर रही है?'

38.**'उजाला योजना'**: ₹70 में एलईडी बल्ब। 35 करोड़ एलईडी बंट चुके, 60,000 करोड़ यूनिट बचत

39.**'पीएम सूर्य घर'**: छत पर सोलर लगाने पर 40% तक सब्सिडी। 300 यूनिट फ्री बिजली

40.**'बीईई स्टार लेबल'**: फ्रिज, एसी खरीदते समय स्टार रेटिंग जरूर देखें

41.**'ऊर्जा साक्षरता अभियान'**: विद्युत मंत्रालय गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है

'कितनी बचत होगी?'

अगर एक 4 लोगों का परिवार ऊपर के 20 टिप्स अपनाए तो:

महीने की बचत: 150-200 यूनिट
पैसे की बचत: ₹1200-₹1600 प्रति माह
साल की बचत:₹15,000 से ₹20, 000

'निष्कर्ष: एक छोटा कदम, बड़ा बदलाव'

श्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं 'ऊर्जा बचत ही ऊर्जा उत्पादन है'। हमें पावर प्लांट कम बनाने हैं तो खपत कम करनी होगी।

'3 गोल्डन रूल याद रखें:'

1.**'स्विच बंद करें'**-काम खत्म, स्विच बंद

2.**'सही तापमान'**- एसी24, फ्रिज 4 डिग्री

3.**'5 स्टार प्रोडक्ट'**- खरीदते समय स्टार रेटिंग देखें

अगली बार जब बिजली का बिल आए तो सोचिए-ये 1200 रुपये आपने बचा लिए। यही पैसे बच्चों की पढ़ाई या घर के लिए लगा सकते हैं। 'आइए प्रण लें-'बिजली बचाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे'

संपर्कः विद्युत मंत्रालय हेल्पलाइन 1912 | http://www.energysave.gov.in

'हम अब टेक्नोलॉजी के नकलची नहीं, निर्माता बनेंगे' : राजनाथ सिंह

@ राष्ट्र समाज

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कहलाने वाला भारत आज 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। आईएनएस विक्रांत, तेजस, ब्रह्मोस और एलसीएच प्रचंड जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म आज हमारी ताकत की पहचान हैं। राजनाथ सिंह जी का स्पष्ट मानना है: 'हम अब टेक्नोलॉजी के नकलची नहीं, निमार्ता बनेंगे'। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ नारा नहीं, हकीकत है।

'आयात से निर्यात' और 'आत्मनिर्भर भारत' का सफर।

राजनाथ सिंह के समय की 7 सबसे सफल उपलब्धियां

1. रक्षा उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि

यही सबसे बड़ा बदलाव है।

उत्पादन : 2014 में ₹46,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹1.50 लाख करोड़ हो गया। ये 90% की वृद्धि है

निर्यात: 2013-14 में सिर्फ ₹686 करोड़ था, जो 2024-25 में ₹23,622 करोड़ से बढ़कर ₹38,000 करोड़ के पार पहुंच गया। यानी 57 गुना बढ़ोतरी

लक्ष्य 2029: उत्पादन ₹3 लाख करोड़ और निर्यात ₹50,000 करोड़

100+ देशों को निर्यात : अब भारत 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहा है

1. ऑपरेशन सिंदूर -'मेड इन इंडिया' का डंका

मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हुई इस कार्रवाई में भारत के

स्वदेशी हथियारों ने अहम भूमिका निभाई।

'राजनाथ सिंह जी ने कहा: ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेड-इन-इंडिया प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा और बढ़ा है' इसमें आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस, आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम -जैसे स्वदेशी सिस्टम ने कामयाबी दिखाई

1.स्वदेशी युद्धपोत व विमान-नौसेना मजबूत

आईएनएस विक्रांत: भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर

आईएनएस महेंद्रगिरी 11 जुलाई 2026 को राजनाथ सिंह जी ने 6वां प्रोजेक्ट 17अ स्टील्थ फ्रिगेट नौसेना में शामिल किया। ये हवा, समुद्र और पानी के अंदर तीनों से लड़ सकता है

97% युद्धपोत स्वदेशी: नौसेना और कोस्ट गार्ड के 97% जहाज अब भारत में ही बनते हैं

1. मिसाइल और हेलीकॉप्टर - तकनीक में आत्मनिर्भरता

एलसीएच प्रचंड: स्वदेशी मल्टी-रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर

तेजस फाइटर जेट: स्वदेशी लड़ाकू विमान का उत्पादन तेज

ब्रह्मोस मिसाइल: उत्पादन बढ़ाया गया

एमपीएटीजीएम: जनवरी 2026 में तीसरी पीढ़ी की 'फायर एंड फॉरगेट' एंटी-टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण

> कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कहलाने वाला भारत आज 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। आईएनएस विक्रांत, तेजस, ब्रह्मोस और एलसीएच प्रचंड जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म आज हमारी ताकत की पहचान हैं।

अग्नि, ब्रह्मोस, आईएनएस अरिहंत: मिसाइल और पनडुब्बी तकनीक में भारत अब विकसित देशों के साथ खड़ा है

1. रक्षा गलियारे और नीतिगत सुधार

2 डिफेंस कॉरिडोर: उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे बने

75% बजट स्वदेशी: रक्षा खरीद का 75% बजट अब सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए आरक्षित

आईडीईई एक्स,अदिति, टीडीआई: स्टार्टअप और निजी कंपनियों को रक्षा में लाने के लिए नई योजनाएं

ओएफबी का निगमीकरण: आयुध फैक्ट्री बोर्ड को 7 कंपनियों में बांटा गया

1. निजी क्षेत्र की भागीदारी

पहले सिर्फ सरकारी डीपीएसयू थे, अब निजी क्षेत्र का योगदान ₹33,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। राजनाथ सिंह जी इसे ₹राष्ट्रीय रक्षा का चौथा स्तंभ₹ कहते हैं

1.रणनीतिक सोच: 'संभावना से आत्मविश्वास तक'

राजनाथ सिंह जी कहते हैं: 'पिछले 12 साल का सफर कमी से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से विकसित भारत तक का है'

3 लाइन में सार पहले: दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक

अब: ₹38,000 करोड़ के हथियार निर्यातक

आगे: 2029 तक ₹50,000 करोड़ निर्यात का लक्ष्य

'3 फोटो': आईएनएस विक्रांत + ब्रह्मोस + एलसीएच प्रचंड

विक्रम-1 : अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय

@ ललित गर्ग

भारत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि यदि संकल्प, वैज्ञानिक दृष्टि और नवाचार का संगम हो तो आकाश भी सीमा नहीं, बल्कि संभावनाओं का प्रारंभ बन जाता है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम-1' का सफल प्रक्षेपण केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था और विज्ञान-प्रधान भविष्य की ओर बढ़ते राष्ट्र का एक नया घोषणापत्र है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 'मिशन आगमन' के अंतर्गत हुई यह ऐतिहासिक उड़ान भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब अंतरिक्ष विज्ञान केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी उद्यम भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का नेतृत्व करेंगे। निश्चित ही विक्रम-1 नए भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय एवं निजी अंतरिक्ष क्रांति की आकाशीय सफलताओं की नई जमीन है।

विक्रम-1 की सफलता उस महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्होंने कभी कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान विलासिता नहीं, बल्कि विकास का अनिवार्य साधन है। आज उसी विचार की आधुनिक अभिव्यक्ति स्काईरूट एयरोस्पेस के रूप में दिखाई देती है, जिसने अपने पहले ही प्रयास में इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस समय दुनिया में केवल कुछ ही देशों के निजी उपक्रम ऑर्बिटल रॉकेट विकसित कर पाए हैं। भारत अब उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है,जहां नवाचार, वैज्ञानिक कौशल और उद्यमशीलता मिलकर नई संभावनाओं का निर्माण कर रहे हैं। अमेरिका के स्पेसएक्स ने जिस निजी अंतरिक्ष क्रांति की शुरूआत की थी,भारत ने अब उसका अपना स्वदेशी संस्करण प्रस्तुत कर दिया है।

विक्रम-1 की तकनीकी विशेषताएं भी इसे विशिष्ट बनाती हैं। पूरी तरह कार्बन कंपोजिट से निर्मित यह रॉकेट अपेक्षाकृत हल्का, अधिक मजबूत तथा कम लागत वाला है। थ्री-डी प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग ने इसके निर्माण खर्च को उल्लेखनीय रूप से कम किया है। इसका सीधा अर्थ है कि भविष्य में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण का वैश्विक बाजार भारत के लिए नए आर्थिक अवसर लेकर

सतीश धवन

आएगा। दुनिया में संचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, रक्षा, आपदा प्रबंधन, इंटरनेट सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों के लिए हजारों छोटे उपग्रहों की आवश्यकता बढ़ रही है। ऐसे में भारत कम लागत व उच्च विश्वसनीयता के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। 'विक्रम-1' को विकसित करने वाली निजी कंपनी 'स्काईरूट एयरोस्पेस' ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर इस रॉकेट का नामकरण कर न सिर्फ उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, हमारे औद्योगिक घरानों को भी यह संदेश दिया है कि कारोबार करते हुए भी अपने देश की समृद्ध विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए।

गौर कीजिए, अप्रैल 1975 में जब भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था, तब उसका नामकरण महान खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था। यह सफलता केवल एक कंपनी की उपलब्धि नहीं है। यह उस नई नीति का परिणाम भी है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश और स्टार्टअप के लिए खोलने का साहसिक निर्णय लिया। नई अंतरिक्ष नीति, इन-स्पेस जैसी संस्थाओं की स्थापना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार प्रावधानों ने भारतीय युवाओं के सामने नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। देश में अनेक स्पेस स्टार्टअप उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष संचार और डेटा सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह परिवर्तन भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगा। किन्तु हर सफलता अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है।

विक्रम-1 की पहली उड़ान सफल अवश्य रही है, परंतु अंतरिक्ष उद्योग में स्थायी सफलता केवल एक प्रक्षेपण से सुनिश्चित नहीं होती। स्काईरूट एयरोस्पेस को अब वैश्विक बाजार में स्पेसएक्स, रॉकेट लैब तथा चीन की अनेक

> विक्रम-1 की सफलता उस महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्होंने कभी कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान विलासिता नहीं, बल्कि विकास का अनिवार्य साधन है।

निजी कंपनियों जैसी सशक्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। नियमित ग्राहक, समय पर प्रक्षेपण, कम लागत, उच्च विश्वसनीयता तथा भविष्य में पुनःप्रयोज्य रॉकेट तकनीक विकसित करना उसकी अगली बड़ी परीक्षा होगी। अंतरिक्ष उद्योग में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है और वह निरंतर सफल अभियानों से ही अर्जित किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक सफलता के बीच एक गंभीर प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा है-क्या इसरो अपनी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रख पाएगा? हाल के वर्षों में अनेक अनुभवी वैज्ञानिक निजी क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए हैं। इसका कारण केवल अधिक वेतन नहीं, बल्कि बेहतर कार्य संस्कृति, अनुसंधान की स्वतंत्रता, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण भी है।

इसरो ने भारत को चंद्रयान,मंगलयान, आदित्य-एल1,गगनयान जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां दी हैं। सीमित संसाधनों में विश्वस्तरीय परिणाम देकर इसरो ने पूरी दुनिया का सम्मान अर्जित किया है। किंतु यदि प्रतिभाशाली वैज्ञानिक धीरे-धीरे संस्थान से बाहर जाते रहे तो दीर्घकाल में अनुसंधान और राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल नए मिशन तैयार करना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रेरित, सम्मानित और संतुष्ट बनाए रखना भी है। सरकार को चाहिए कि इसरो के वैज्ञानिकों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन संरचना, अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं, निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां विकसित करे। सरकारी संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग का वातावरण तैयार होना चाहिए। निजी क्षेत्र इसरो का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहयोगी बन सकता है। जिस प्रकार अमेरिका में नासा और स्पेसएक्स मिलकर अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, उसी प्रकार भारत में इसरो और निजी कंपनियों का समन्वय देश को वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

अंतरिक्ष विज्ञान को विद्यालयों और विश्व विद्यालयों के स्तर तक पहुंचाया जाए। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं का विषय न रहकर जन-आंदोलन बने। युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नवाचारकताओं को स्टार्टअप संस्कृति से जोड़ने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। यदि प्रत्येक राज्य में स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएं,उद्योगों व विश्व विद्यालयों के बीच अनुसंधान साझेदारी विकसित की जाए,अंतरिक्ष तकनीक में निवेश को बढ़ावा दिया जाए तो भारत अगले दशक में विश्व का अग्रणी अंतरिक्ष नवाचार केंद्र बन सकता है। भविष्य की आकाशीय सफलताओं की नई जमीन तैयार करने के लिए कुछ रचनात्मक कदम अत्यंत आवश्यक हैं-इसरो व निजी कंपनियों के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ हों;पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक व हरित प्रणोदन (ग्रीन प्रोपल्शन) पर विशेष निवेश किया जाए;अंतरिक्ष विनिर्माण के लिए स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाए।

@ राष्ट्र समाज

धंसती सड़कें और भ्रष्टाचार की गहरी नींव

आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीक के इस युग में ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं। यह विकास नहीं, बल्कि विकास के नाम पर जनता के साथ किया गया विश्वासघात है। सड़कें और पुल किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति की धमनियां होते हैं। इनके माध्यम से व्यापार चलता है, गांव शहरों से जुड़ते हैं, किसान अपनी उपज बाजार तक पहुंचाते हैं व आम नागरिक सुरक्षित आवागमन करते हैं। जब यही आधारभूत संरचनाएं असमय ध्वस्त होने लगें, तो केवल कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं टूटता, जनता का शासन व प्रशासन पर विश्वास भी टूटता है।

जिस दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को आधुनिक भारत के तेज, सुरक्षित और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसकी सड़क उद्घाटन के महज ढाई महीने बाद पहली ही बरसात में धंस गई। सड़क इस तरह धंसी कि कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया। प्रश्न यह है कि करोड़ों रुपये की लागत से बनी सड़क पहली ही वर्षा का सामना क्यों नहीं कर सकी? क्या निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया? क्या जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं थी? या फिर यह भ्रष्टाचार, लापरवाही और जवाबदेही के अभाव का परिणाम है? यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में नई सड़कों,पुलों,फ्लाई ओवरों व सार्वजनिक भवनों के ध्वस्त होने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग एक दर्जन छोटे-बड़े पुलों का गिर जाना पूरे देश को झकझोर गया था। एक ही दिन 5 पुल-पुलियों का धराशायी होना केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का जीवंत प्रमाण था। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की जान चली गई। कोलकाता के विवेकानंद फ्लाईओवर के गिरने से अनेक परिवार उजड़ गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 की छत गिरने की घटना और मुंबई के घाटकोपर में विशाल होर्डिंग गिरने से हुई मौतों ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक निर्माण की गुणवत्ता गंभीर संकट से गुजर रही है।

इन घटनाओं को केवल प्राकृतिक आपदा या भारी वर्षा का परिणाम बताकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। यदि पहली ही बारिश में

सड़क धंस जाए, पुल बह जाएं या भवनों की छतें गिर जाएं, तो यह प्रकृति की नहीं, बल्कि मानव निर्मित विफलता की एवं गहरे में पैठे भ्रष्टाचार की कहानी है। आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीक के इस युग में ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं। यह विकास नहीं, बल्कि विकास के नाम पर जनता के साथ किया गया विश्वासघात है। सड़कें और पुल किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति की धमनियां होते हैं। इनके माध्यम से व्यापार चलता है, गांव शहरों से जुड़ते हैं, किसान अपनी उपज बाजार तक पहुंचाते हैं व आम नागरिक सुरक्षित आवागमन करते हैं। जब यही आधारभूत संरचनाएं असमय ध्वस्त होने लगें, तो केवल कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं टूटता, जनता का शासन और प्रशासन पर विश्वास भी टूटता है।

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़क धंसने के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संबंधित प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर को निलंबित किया तथा निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल निलंबन से समस्या का समाधान हो जाएगा? अनुभव बताता है कि अधिकांश मामलों में निलंबित अधिकारी कुछ समय बाद बहाल हो जाते हैं या उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। जिन कंपनियों को काली सूची में डाला जाता है, वे कुछ समय बाद नए नाम से फिर सरकारी ठेके प्राप्त करने लगती हैं। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार का चक्र लगातार चलता रहता है। वास्तविक समस्या जवाबदेही के अभाव की है। निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया-डिजाइन, सामग्री, तकनीकी परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय नहीं होती। जब दोषियों को कठोर दंड नहीं मिलता, तब भ्रष्टाचार को अप्रत्यक्ष संरक्षण मिल जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष बरसात के साथ सड़कें उखड़ती हैं, पुलों में दरारें पड़ती हैं और करोड़ों रुपये की परियोजनाएं समय से पहले दम तोड़ देती हैं।

देश में सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ जाता है। ठेके हासिल करने से लेकर बिलों के भुगतान तक अनेक स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब परियोजना की लागत का बड़ा भाग अवैध लेन-देन में खर्च हो जाता है, तब निर्माण की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। घटिया सामग्री का उपयोग, तकनीकी मानकों की अनदेखी और समय सीमा का दबाव मिलकर ऐसी संरचनाएं तैयार करते हैं जो पहली ही परीक्षा में असफल हो जाती हैं। विडंबना यह भी है कि प्रत्येक दुर्घटना के बाद जांच समितियां गठित होती हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, मुआवजे घोषित होते हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आता। दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते हैं। जनता का आक्रोश धीरे-धीरे शांत हो जाता है और फिर कोई नई दुर्घटना उसी कहानी को दोहरा देती है। विकसित देशों में भी दुर्घटनाएं होती हैं, किंतु वहां प्रत्येक हादसे के बाद प्रणालीगत सुधार किए जाते हैं। भारत में सुधार की अपेक्षा लीपापोती अधिक दिखाई देती है।

अब समय आ गया है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। प्रत्येक परियोजना के लिए स्वतंत्र थर्ड-पार्टी गुणवत्ता ऑडिट अनिवार्य किया जाए। निर्माण सामग्री की डिजिटल ट्रैकिंग, प्रत्येक चरण का तकनीकी सत्यापन तथा ड्रोन और आधुनिक सेंसर आधारित निरीक्षण को व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। परियोजना पूरी होने के बाद केवल उद्घाटन नहीं, बल्कि निश्चित अवधि तक उसके प्रदर्शन का भी वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि दोषी अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों की व्यक्तिगत एवं आर्थिक जवाबदेही तय हो। यदि उनकी लापरवाही से जनहानि होती है या सार्वजनिक धन की बबार्दी होती है, तो केवल निलंबन नहीं, बल्कि सेवा से बर्खास्तगी, आर्थिक दंड और आपराधिक मुकदमे जैसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे, आर्थिक गलियारे, हाई-स्पीड रेल, आधुनिक हवाई अड्डे और स्मार्ट शहर तभी सार्थक होंगे, जब उनकी नींव ईमानदारी, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर आधारित होगी। विकास का अर्थ केवल नई परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि उनका वर्षों तक सुरक्षित व टिकाऊ बने रहना भी है। आज केवल नई सड़कें और पुल बनाने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें कोई भी सड़क पहली बारिश में न धंसे, कोई पुल उद्घाटन से पहले न गिरे और कोई हवाई अड्डा यात्रियों के लिए खतरा न बने। भ्रष्टाचार की गहरी नींव पर विकास की मजबूत इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। यदि भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनना है, तो विकास की चमक के साथ उसकी गुणवत्ता, पारदर्शिता व जवाबदेही को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। तभी जनता का विश्वास बचेगा, सार्वजनिक धन सुरक्षित रहेगा और विकास का मार्ग सचमुच मजबूत एवं स्थायी बन सकेगा।

समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस,
गणेश चतुर्थी एवं कृष्ण जन्माष्टमी की
हार्दिक
शुभकामनाएं
विनीत कुमार गुप्ता
(लोहिया ग्रुप)

समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस,
गणेश चतुर्थी एवं कृष्ण जन्माष्टमी की
हार्दिक
शुभकामनाएं
मधुसुदन अग्रवाल
(हल्दीराम)

समस्त देशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्थी
एवं कृष्ण जन्माष्टमी की
हार्दिक
शुभकामनाएं
सतीराम
यादव
(बीटीडब्ल्यू)

समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस,
गणेश चतुर्थी एवं कृष्ण जन्माष्टमी की
हार्दिक
शुभकामनाएं
श्याम सुन्दर अग्रवाल
(बिकानेरवाला)

समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस,
गणेश चतुर्थी एवं कृष्ण जन्माष्टमी की
हार्दिक
शुभकामनाएं
15
अशोक गुप्ता
(सकरनी)

समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस,
गणेश चतुर्थी एवं कृष्ण जन्माष्टमी की
हार्दिक
शुभकामनाएं
अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी
धर्मगुरू रंजित जी
महाराज

भावनाओं का 'अवसरवादी आहतपन'

@ निर्मल रानी

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे में कथित हेराफेरी के मुद्दे को उठाने के मकसद से गत 31 जुलाई को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में साधू के वेश में एक प्रतीकात्मक नाटक किया था। इस दौरान विपक्ष के भी कई नेता वहां मौजूद रहे। इसी प्रदर्शन में राहुल गांधी ने प्रतीकात्मक रूप से दानपात्र में पैसे डालने का प्रयास किया। इसके बाद पप्पू यादव ने दानपेटी लेकर भागने का नाटक किया और समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने उन्हें पकड़ने का अभिनय किया। इस नाट्य मंचन रुपी प्रदर्शन के बाद भाजपा,विश्व हिंदू परिषद , बजरंग दल, व इसके समर्थक संत समाज ने इसे सनातन धर्म और साधु-संतों की छवि का अपमान बताया। सत्ता समर्थक कई संतों ने भी आरोप लगाया कि पप्पू यादव द्वारा संसद में 'इस प्रकार भगवा वस्त्र और साधू का रूप धारण कर व इसका नाट्य मंचन कर साधु वेश का मजाक उड़ाया गया है, जिससे सनातन धर्म और संतों की आस्था को ठेस पहुंची है। लिहाजा इस मामले के विरोध में भाजपा नेताओं और धार्मिक संगठनों ने कानूनी कदम उठाए। दिल्ली, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, मथुरा, नागपुर, जम्मू सहित देश के अन्य कई शहरों में पप्पू यादव, राहुल गांधी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर कहीं पुलिस में शिकायतें व एफ आईआर दर्ज की गईं तो कहीं विरोध प्रदर्शन किये गये। कई मठों, मंदिरों और अखाड़ों ने पप्पू यादव के प्रवेश पर रोक लगाने और संसद से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। लोकसभा स्पीकर ने भी इसतरह का प्रदर्शन करने पर नाराजगी जताई और इसे संसदीय गरिमा के विरुद्ध बताया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर तो विभिन्न हिंदू संगठनों और अनेक साधु-संतों ने एकत्रित होकर 'सद्बुद्धि हवन' और धार्मिक अनुष्ठान किया। इसके अलावा दिल्ली में पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन के आधिकारिक आवास के बाहर हिंदू संगठनों ने जोरदार नारेबाजी की और उनका सामाजिक व धार्मिक बहिष्कार करने की मांग की।

इसी बीच सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर उन पर हमले की कोशिश हुई है, जहां गत 2 अगस्त को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दो युवकों ने पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी और कथित तौर पर उन पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद सांसद समर्थकों ने दो आरोपियों को तुरंत

पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इन हमलावर आरोपियों का भी यही कहना था पप्पू यादव द्वारा सनातन धर्म, साधु-संतों और भगवा वस्त्रों का कथित तौर पर अपमान किया गया है और वे इसी पर आपत्ति जताने वहां गये थे। उधर पप्पू यादव ने भी दावा किया है कि उन्हें लगातार जान से मारने और जिंदा जलाने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वे इससे डरने वाले नहीं हैं।

सांसद उदित राज व शिवसेना सांसद संजय राउत जैसे अनेक नेताओं ने पप्पू यादव से मिलकर उनके प्रति समर्थन भी व्यक्त किया है। इन नेताओं ने पप्पू यादव पर हुये हमले को 'कायराना' करार देते हुए कहा कि पप्पू यादव ने राम मंदिर के चंदे में हुई कथित हेराफेरी का मुद्दा उठाकर कुछ भी गलत नहीं किया। इन नेताओं ने प्रदर्शन का पुरजोर समर्थन किया था। इन नेताओं ने कहा कि भगवा रंग किसी पार्टी के नाम रजिस्टर्ड नहीं है और पप्पू यादव ने चंदा चोरी की झांकी दिखाकर सही सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संसद परिसर के भीतर और बाहर इस पूरे विवाद में पप्पू यादव की लड़ाई का समर्थन किया। पप्पू यादव ने भी कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था और सनातनी विचारों को बचाने के लिए उनके साथ खड़े हैं।

परंतु समय समय पर लोगों की 'धार्मिक भावनाएं ' आहत होने को लेकर देश में यह सवाल भी पूछा जाने लगा है कि जब सत्ताधारी नेताओं द्वारा न केवल साधु वेशभूषा का बल्कि सीधे देवी देवताओं तक का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है उस समय आखिर इन लोगों की भावनायें कहां चली जाती हैं ? याद कीजिये जब गत 4 जुलाई को भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर आए थे उस समय एयरपोर्ट से भाजपा मुख्यालय तक एक रोड शो आयोजित किया गया था।

इस रोड शो के दौरान एक कलाकार भगवान हनुमान का वेश-रूप धारण किए अपने हाथ में भाजपा का झंडा लेकर नितिन नवीन के काफिले के ठीक आगे नाच रहा था। इस दौरान नितिन नवीन सहित अनेक नेता हनुमान का नृत्य देख 'रथ' के ऊपर खड़े होकर मुस्कुराते नजर आ रहे थे। तो क्या भाजपा के राजनीतिक रोड शो के लिए भगवान के स्वरूप का इस्तेमाल करना, भगवान हनुमान के स्वरूप को अपने स्वागत में सड़कों पर नचाना, क्या यह कृत्य हिंदू भावनाओं का अनादर करने वाला कृत्य नहीं था? क्या यह राजनीति के लिए भगवान के स्वरूप का दुरुपयोग नहीं था?

इसी तरह जनवरी 2026 में अहमदाबाद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव के दौरान साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल हुए थे। दोनों नेताओं ने वहां पतंग उड़ाई थी। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर ने जिस विशेष पतंग को हवा में उड़ाया था, उस पर भगवान हनुमान की तस्वीर बनी हुई थी। क्या करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव भगवान हनुमान की तस्वीर को पतंग बनाकर हवा में उड़ाना देवताओं का मजाक उड़ाना नहीं है? उस समय इन्हीं हिंदू संगठनों की भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई थीं? इसी तरह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भगवान गणेश की कुछ ऐसी मूर्तियां स्थापित की गई थीं, जिन्हें आरएसएस का आधिकारिक गणवेश यानी सफेद शर्ट, खाकी हाफ पैंट और काले जूते पहनाया गया था। यहां तक कि भगवान गणेश के साथ-साथ उनके वाहन चूहे को भी संघ की ड्रेस पहनाई गई थी। इस मूर्ति में भगवान गणेश और मूषक को संघ की शाखाओं की तरह 'ध्वज प्रणाम' की मुद्रा में सीने पर हाथ रखकर खड़ा दिखाया गया था और उनके हाथों में संघ का भगवा झंडा भी थमाया गया था। क्या पप्पू यादव के साधू बनने पर आक्रोशित होने वालों ने उस समय यह सवाल उठाया था कि 'हमारे आराध्य देव भगवान गणेश को आरएस एस का साधारण 'कार्यकर्ता' या 'स्वयंसेवक' बनाकर पंडालों में क्यों नचाया और खड़ा किया गया?' क्या यह भगवान का अपमान और राजनीति के लिए उनका दुरुपयोग नहीं है? उस समय किसी भी हिंदू संगठन या संत समाज की भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई थीं? इसके अलावा भी हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भगवानों देवी देवताओं व संतों की वेश भूषा अपमानित होती नजर आती है तथा धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। ऐसे में धार्मिक भावनाओं का आहत होना भी स्वाभाविक तो जरूर है परंतु भावनाओं का 'अवसरवादी आहतपन' समझ से परे है।

विधानसभा उपचुनावों के परिणाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट से भाजपा को बेहद संतोष देने वाली खबर मिली है। यहां पर भाजपा प्रत्याशी सतेंद्रभाई पटेल ने 30,630 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी भीखाभाई रबारी को हरा दिया है।यहां पर भी भूपेंद्रभाई रजनीकांत पटेल के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है।'

उपचुनाव परिणाम का स्पष्ट संदेश

@ दीपक कुमार त्यागी

तीन विधानसभा के उपचुनावों के परिणाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा के विषय बन गये हैं, क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार हैं और उपचुनावों में सत्ता में काबिज पक्ष को चुनावी रणभूमि में जीतना बेहद आसान होता है। लेकिन सत्ता में होने के बाद भी बिहार, मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनावों में बेहद हाईप्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर और दतिया में भाजपा प्रत्याशियों की हार कहीं पार्टी के अश्वमेध यज्ञ के विजयी घोड़े की चाल को आने वाले समय के चुनावों में खराब ना कर दें। हालांकि भाजपा के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व की यह खूबी है कि वह अपनी गलतियों को पहचान कर के उन पर सुधार की अन्य दलों की तरह केवल कागजों में खानापूर्ति नहीं करता है, वह गलतियों को धरातल पर सुधार करता है।'

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के झटके से भारतीय जनता पार्टी अभी उभर भी नहीं पायी थी कि बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के परिणाम से भाजपा को जबरदस्त झटका लगा है। बिहार की हाईप्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तो जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर (पीके) ने बड़ी जीत दर्ज की है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को 64151 मत मिले, उन्होंने भाजपा के नीरज कुमार को 19324 मतों के भारी भरकम अंतर से हराया है। भाजपा के नीरज कुमार को 44827 मत मिले, वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी को 14273 मत मिले हैं। यहां भाजपा के लिए विचारणीय बात यह है कि इस सीट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पांच पर विधायक रह चुके हैं और उनके इस्तीफे के बाद ही यह सीट खाली हुई थी। वैसे तो भाजपा बांकीपुर में लगातार 30 वर्षों से जीतती आ रही थी और इस विधानसभा सीट को भाजपा का सुरक्षित गढ़ माना जाता था, लेकिन प्रशांत किशोर (पीके) ने इस सीट के उपचुनाव में उतरकर भाजपा के इस सुरक्षित गढ़ को बुरी तरह से ढहा दिया है। जबकि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। मेरा बूथ सबसे मजबूत के सिद्धांत पर कार्य करने वाली भाजपा के लिए इस सीट पर हार बहुत बड़ा झटका है, विपक्षी दल इस सीट के हारने का डंका अब पूरे देश में जोर-शोर से बजायेंगे। 'हालांकि विधानसभा उपचुनावों के परिणाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट से भाजपा को बेहद संतोष देने वाली खबर मिली है। यहां पर भाजपा प्रत्याशी सतेंद्रभाई पटेल ने 30,630 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी भीखाभाई रबारी को हरा दिया है। यहां पर भी भूपेंद्रभाई रजनीकांत पटेल के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है।'

वहीं उपचुनावों के परिणाम में बिहार के बाद रही-सही कसर को मध्यप्रदेश ने पूरा कर दिया, वहां पर भी मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। लेकिन फिर भी बेहद ही हाईप्रोफाइल विधानसभा सीट दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 6016 मतों से भाजपा के आशुतोष तिवारी को हरा दिया है। घनश्याम

सिंह को 66757 मत मिले, आशुतोष तिवारी को 60741 मत मिले, वहीं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रत्याशी दामोदर यादव 'मंडल' ने 22527 मत लेकर के भाजपा का खेल पूरी तरह से खराब करते हुए भविष्य के लिए खतरें का अलार्म भी बजा दिया है। हालांकि फिलहाल तो इस सीट कांग्रेस के राजेंद्र भारती विधायक थे, लेकिन अप्रैल 2026 में एक अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के कारण से इस सीट पर उपचुनाव हुए।

लेकिन वर्ष 2018 में इस सीट से भाजपा के हाईप्रोफाइल दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा विधायक रहे थे, लेकिन वर्ष 2023 में वह कांग्रेस के राजेंद्र भारती से चुनाव हार गए थे, लेकिन हार के बाद भी वह क्षेत्र में दिन-रात सक्रिय थे और उन्हें व उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि भाजपा का नेतृत्व उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा पर ही दांव खेलेगा, लेकिन पार्टी हाईकमान ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देकर के आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने सड़क पर जमकर के बवाल काटा था, हालांकि भाजपा में सड़कों पर ऐसा विद्रोह शायद ही कभी देखने को मिला हो, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेताओं से लेकर के कार्यकर्ताओं तक को भी बेहद अनुशासित माना जाता है, सड़कों पर हुए विवाद के चलते ही दतिया में पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ा है।

भाजपा नेतृत्व के लिए बांकीपुर व दतिया उपचुनाव के परिणाम की स्थिति आत्ममंथन करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के हितों को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए भाजपा के शीर्ष रणनीतिकारों को उपचुनावों में मिली करारी हार के कारणों का बारीकी से आंकलन करते हुए कमियों पर आत्ममंथन अवश्य करना चाहिए। उन्हें यह अवश्य देखना चाहिये कि आखिर दतिया व बांकीपुर विधानसभा जैसे गढ़ में पार्टी की यह स्थिति क्यों हुई। शीर्ष नेतृत्व को समय रहते जनता की नब्ज को पहचानने का कार्य कर लेना चाहिए।

नेतृत्व व रणनीतिकारों को पार्टी हित में निष्पक्ष रूप से यह मंथन अवश्य करना चाहिए कि कहीं पार्टी से नये मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति दशकों से पार्टी की गोद में बैठे हुए पुराने मतदाताओं को पार्टी से छिटकाने का कार्य तो नहीं कर रही है। पार्टी में नेताओं का एक धड़ा जिस तरह से हिन्दुत्व की जड़ों को मजबूत करने की जगह हिन्दुओं को अगड़े व पिछड़े में बांटकर के क्षणिक स्वार्थों की पूर्ति करने के कार्य किया लगा हुआ है, वह हार के प्रमुख कारणों में से एक है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है।

पार्टी नेतृत्व को समय रहते ही समझना चाहिए कि मोदी-शाह की जोड़ी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निस्वार्थ भाव से लगे स्वयंसेवकों ने दिन-रात मेहनत करके हिन्दुओं में बने कास्ट के बैरियर को तोड़कर के भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया था, तब जाकर ही भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाते हुए देश के विभिन्न राज्यों की सत्ता पर काबिज हो पायी थी। भाजपा को फिर से हिन्दुओं को एकजुट करने के लिए धरातल पर कार्य करना होगा, हिन्दुओं के मस्तिष्क में अपनी कार्यशैली में नजर आने वाला हिंदुत्व का सच्चा पहरेदार बनना होगा, भीडतंत्र के दवाब में आये बिना देश को नियम कायदे कानून के राज से चलाना होगा, देश में समान नागरिक संहिता व जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून बनाकर लागू करने होंगे, तब ही आने वाले समय में भाजपा का भविष्य देश में सुरक्षित है।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग का स्तर लगातार गिरता और नया रूप ले रहा है, जहां व्यक्तिगत बयानों से लेकर रणनीतिक बदलावों तक हर बात पर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर किया गया करारा तंज इस राजनीतिक उथल-पुथल का ताजा उदाहरण है।

मुखर योगी और अखिलेश की सियासी कशमकश

@ संजय सक्सेना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं। बबुआ भी यही करते थे। वो दोपहर 12 बजे सो कर उठते थे। दो बजे तैयार होते थे। पांच बजते-बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और शाम 7 बजे महफिल सज जाती थी। देश-प्रदेश के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही कहां होता था। प्रदेश की कानून-व्यवस्था का हाल तो ये था कि महिलाओं को सबसे बड़ा खतरा इन्हीं सपाइयों से ही था। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब सरकारें प्रदेश के विकास के लिए काम करती हैं तो उसका लाभ समाज के हर तबके को मिलता है। दरअसल, अखिलेश यादव आजकल कोई भी बात सीधे नहीं कहते हैं। उनकी भाषा में तंज ज्यादा और साफगोई कम नजर आती है। वह जो भी मुद्दे उठाते हैं, उसमें भी वह अपने सियासी फायदे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हर घटना का नाटकीय रूपांतरण कर देते हैं। चंदा चोरी में भी यही देखने को मिल रहा है। उनके सांसद और नेता हर जगह कथित रूप से दानपात्र लेकर हर जगह दिखाई पड़ने लगे हैं। आजकल अखिलेश ने सॉफ्ट हिन्दुत्व के चक्कर में मुस्लिम वोट बैंक की सियासत को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस पर ओवैसी उन पर हमेशा हमलावर रहते हैं। वहीं कुछ मुसलमान तो यहां तक कहते हैं कि अखिलेश ने जिस धर्म में जन्म नहीं लिया, वह उसके नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। यही बात ओवैसी भी मुसलमानों को समझाने में लगे हैं। अखिलेश के पीडीए का भी यही हाल है। कभी वह पीडीए को पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक बताते हैं तो कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा-दलित और ए का मतलब आधी आबादी बताने लगते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पीडीए में पीडी को पंडितों का शॉर्ट फॉर्म बता दिया। बात-बात पर उनके जनप्रतिनिधि संसद से लेकर विधानसभा तक हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में प्रदर्शन करते हैं। हाल यह है कि कोई पत्रकार उनसे सख्त सवाल पूछ लेता है तो वह उसे गोदी मीडिया और बीजेपी वाला बता देते हैं।

दुखद यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग का स्तर लगातार गिरता और नया रूप ले रहा है, जहां व्यक्तिगत बयानों से लेकर रणनीतिक बदलावों तक हर बात पर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर किया गया करारा तंज इस राजनीतिक उथल-पुथल का ताजा उदाहरण है। इस बयान के साथ-साथ अखिलेश यादव की बदलती कार्यशैली, सॉफ्ट हिंदुत्व के समीकरण व उनके पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक/आधी आबादी) फॉर्मूले पर उठ रहे सवाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत कुछ संकेत देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की कार्यशैली और दिनचर्या पर सीधा कटाक्ष करते हुए उनकी राजनीतिक गंभीरता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जीवनभर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ कहकर संबोधित करते हुए उनकी दिनचर्या का मजाक उड़ाया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, दोपहर 12 बजे सो कर उठना, दो बजे तैयार होना, 5 बजे जिम जाना और शाम 7 बजे महफिल सजाना एक जननेता की पहचान नहीं हो सकती है। इस प्रकार के बयानों के जरिए सत्ता पक्ष जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश करता है कि विपक्ष के नेता जमीनी हकीकत, जनता के दुखों और प्रदेश के विकास के प्रति गंभीर नहीं हैं। इसके अलावा, कानून-व्यवस्था के मुद्दे को जोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने पिछली सपा

सरकार के कार्यकाल को याद दिलाया और आरोप लगाया कि उस दौरान महिलाओं को सबसे बड़ा खतरा सपाइयों से ही था। यह राजनीतिक बयानबाजी केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि यह भाजपा की उस स्थापित रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह विपक्ष को 'विशेषाधिकार प्राप्त' और 'जमीनी हकीकत से कटे हुए' वर्ग के रूप में चित्रित करती है।

उधर, अखिलेश यादव की वर्तमान राजनीतिक रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जिसे कई राजनीतिक विश्लेषक सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव मान रहे हैं। इस चक्कर में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है या उसे कुछ हद तक ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यही कारण है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार अखिलेश यादव और सपा पर हमलावर रहते हैं।

ओवैसी और समुदाय के कुछ आलोचकों का यह तर्क तेजी से जमीन पकड़ रहा है कि जो नेता अपने मूल धार्मिक और वैचारिक दायरे में स्पष्ट नहीं है, वह दूसरों के लिए कितना वफादार साबित होगा। मुस्लिम समाज के एक वर्ग में यह भावना घर कर रही है कि सपा केवल चुनावों के वक्त उनके वोटों का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन उनके वास्तविक मुद्दों पर खुलकर सामने आने से बचती है। यह असमंजस समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, मुस्लिम-यादव (एमवाई) समीकरण ही पार्टी की राजनीतिक ताकत का मुख्य आधार रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नया राजनीतिक मंत्र गढ़ा था, लेकिन इसके बार-बार बदलते अर्थों ने राजनीतिक गलियारों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक बताया जाता है,तो कभी इसे आधी आबादी (महिलाएं) से जोड़ा जाता है।

हाल ही में पीडी के दायरे में पंडित (सवर्ण वर्ग) को शामिल करने के संकेतों ने इस फॉर्मूले की वैचारिक स्पष्टता पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। जबकि हो यह है कि जब किसी राजनीतिक नारे या समीकरण का दायरा बहुत अधिक फैला दिया जाता है, तो उसका मूल वैचारिक उद्देश्य कमजोर पड़ने लगता है। पिछड़ों और दलितों के अधिकारों की बात करने वाली पार्टी यदि अचानक सवर्ण जातियों को भी इसी खेमे में फिट करने की कोशिश करती है, तो इससे मूल कार्यकताओं के बीच भ्रम फैलता है। आलोचकों का मानना है कि यह सब केवल तात्कालिक चुनावी नफा-नुकसान को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिसमें दूरगामी वैचारिक दृढ़ता का अभाव साफ झलकता है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव की राजनीतिक शैली में अब आक्रामकता और तंज की प्रधानता बढ़ गई है। वह किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर सीधी बात करने के बजाय सियासी नफा-नुकसान को तरजीह देते हैं। इसके साथ ही, हालिया दौर में उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा संसद से लेकर विधानसभा तक किए जाने वाले हंगामे और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सीमाओं को लांघने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं।

जब मीडिया द्वारा उनसे कोई कड़े या तीखे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसे गोदी मीडिया या भाजपा का प्रवक्ता कहकर टाल देना राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक नहीं माना जाता है। एक बड़े राजनीतिक दल के मुखिया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आलोचनाओं का सामना तर्कों के साथ करे, न कि उन्हें खारिज करके। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि विपक्ष असहज करने वाले सवालों से बचने का रास्ता तलाश रहा है, जो लोकतांत्रिक संवाद के लिहाज से स्वस्थ परंपरा नहीं है। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह मुकाबला केवल दो दलों की वैचारिक लड़ाई नहीं, बल्कि कार्यशैली, विश्वसनीयता और बदलते समीकरणों की एक लंबी और जटिल शतरंज की चाल बन चुका है।

भारत की विकास यात्रा तब तक पूर्ण नहीं कही जा सकती जब तक जल, जंगल और जमीन से जुड़ा वह समाज, जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति की रक्षा की है, सम्मान और समान अवसर के साथ राष्ट्रीय प्रगति का अभिन्न भाग न बने। आदिवासी समाज ने कभी प्रकृति का दोहन नहीं किया, बल्कि उसका संरक्षण किया।

प्रकृति के संरक्षक हैं आदिवासी

@ राष्ट्र समाज

विश्व आदिवासी दिवस केवल एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन भर नहीं है, बल्कि यह उस मूल चेतना का अभिनंदन है जिसने मानव सभ्यता को प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की कला सिखाई। भारत के आदिवासी समुदाय केवल जनसंख्या का एक वर्ग नहीं हैं, बल्कि वे इस राष्ट्र की सांस्कृतिक स्मृति, पर्यावरणीय संतुलन, आध्यात्मिक संवेदना और स्वाधीनता चेतना के जीवंत प्रतिनिधि हैं। यदि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु भारत की संकल्पना को वास्तविक अर्थों में साकार करना है, तो आदिवासी समाज को विकास का विषय नहीं, बल्कि विकास का सहभागी और नेतृत्वकर्ता बनाना होगा। भारत की विकास यात्रा तब तक पूर्ण नहीं कही जा सकती जब तक जल, जंगल और जमीन से जुड़ा वह समाज, जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति की रक्षा की है, सम्मान और समान अवसर के साथ राष्ट्रीय प्रगति का अभिन्न भाग न बने। आदिवासी समाज ने कभी प्रकृति का दोहन नहीं किया, बल्कि उसका संरक्षण किया। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संकट और जैव विविधता के संरक्षण की चिंता कर रही है, तब आदिवासी जीवन-दर्शन आधुनिक विश्व के लिए एक वैकल्पिक विकास मॉडल प्रस्तुत करता है।

आदिवासी प्रकृति के पुत्र और संस्कृति के प्रहरी है। 'जो प्रकृति से जुड़ा है, वही मनुष्यत्व का संरक्षक है'-यह वाक्य आदिवासी समाज पर अक्षरशः लागू होता है। आदिवासी शब्द मात्र एक सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि एक दर्शन है, सहजता, सामूहिकता, संतुलन और सह-अस्तित्व का दर्शन। करीब 90 प्रतिशत खनिज सम्पदा, वनौषधियां और जैव विविधता इन्हीं के क्षेत्रों में विद्यमान है। उनका जीवन सभ्यता के केंद्र से नहीं, बल्कि संवेदना के मूल से संचालित होता है। वे भले ही 'वनवासी' कहलाए गए, परंतु उनका जीवनदर्शन हमें शहरीकरण के आडंबर से बाहर निकालकर स्वाभाविक जीवन की राह दिखाता है। नए भारत में विकास का पर्याय यदि केवल बहुराष्ट्रीय निवेश, चकाचौंध और स्मार्ट सिटी बन गया है, तो आदिवासी समाज उसके विस्थापित मूल्य हैं। जल-जंगल-जमीन के नाम पर किए गए सौदे, खनिज लूट, धार्मिक कन्वर्जन, सांस्कृतिक विघटन और जबरन भूमि अधिग्रहण की घटनाएं केवल उनकी आर्थिक दशा ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि उनकी पहचान, भाषा और परंपरा को भी निगलती जा रही हैं। आज आदिवासी समाज ऋण, अशिक्षा, पलायन, अस्वास्थ्यकर जीवन, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। तथाकथित विकास ने उन्हें 'पराया' बना दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परायेपन का दूर करने के लिए पिछले वर्षों में जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तीकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में स्थान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय हो, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी व कौशल विकास की योजनाओं का विस्तार हो, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का व्यापक विस्तार हो, अथवा प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी पहलें-इन सबने यह स्पष्ट किया है कि नए भारत की विकासधारा में आदिवासी समाज को केंद्र में रखने का प्रयास किया जा रहा है। यह केवल योजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण में परिवर्तन का संकेत है। किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि किसी भी सरकारी योजना की सफलता तभी सुनिश्चित होती है, जब समाज के भीतर से ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व सामने आएं जो सेवा, संस्कार और संगठन के माध्यम से परिवर्तन की चेतना जगाएं। गुजरात के सुप्रसिद्ध जैन संत डॉ. गणि राजेन्द्र विजयजी ने इसी दिशा में पिछले दो-तीन दशकों में जो कार्य किया है।

BIKANO is our range of Packaged Namkeens, Sweets, Sherbets, Papad and Pickles with a dependable shelf life. These are popular not only in India but also in the quality conscious overseas markets like Europe, America, Canada, Middle East and many more

VISIT BIKANERVALA OUTLETS IN : INDIA | USA | CANADA | U.A.E. | QATAR | BAHRAIN | UNITED KINGDOM | NEW ZEALAND | SINGAPORE | NEPAL

FOR BULK ORDER / BOOKINGS CALL 9528 214 214, 9971 877 211

Corporate Address: **BIKANERVALA PVT. LTD.** A-27, Lawrence Road Industrial Area, New Delhi - 110035

'अयोध्या के रणबांकुरे' अपर पुलिस आयुक्त डा. राजीव नारायण मिश्र

@ राष्ट्र समाज

एक जांबाज, तकनीक-प्रिय और जनसेवी पुलिस अधिकारी का संक्षिप्त परिचय और पारिवारिक पृष्ठभूमि

डॉ. राजीव नारायण मिश्रा भारतीय पुलिस सेवा के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 30 अक्टूबर को कानपुर नगर में विजयादशमी के दिन हुआ था। उनके पिता उत्तर प्रदेश सरकार में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे और माता मनोरमा मिश्रा शिक्षित गृहिणी थीं तथा साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त थीं। पिता के तबादलों के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई। बाद में उन्होंने कानपुर में माध्यमिक और उच्च शिक्षा पूरी की। शैक्षणिक रूप से वे बेहद प्रतिभाशाली रहे झ क्राइस्टचर्च कॉलेज, कानपुर से बीकॉम और एमकॉम की डिग्री, रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से पीएचडी। आईपीएस बनने से पहले उन्होंने एक निजी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी और पीएनएन डिग्री कॉलेज कानपुर में प्रवक्ता के रूप में भी काम किया।

पीसीएस से आईपीएस तक का सफर

राजीव नारायण मिश्रा ने अपना करियर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस अधिकारी के रूप में खंडवा जिले में शुरू किया। लेकिन उनका लक्ष्य आईपीएस था जिसे उन्होंने मेहनत से हासिल किया और 2010 बैच में आईपीएस बने।

सेवा में नियुक्तियां और कार्यक्षेत्र

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी पहली नियुक्ति वाराणसी में हुई। इसके बाद उन्होंने अयोध्या, बरेली, मेरठ, नोएडा, कुशीनगर और लखनऊ जैसे संवेदनशील जिलों में विभिन्न पदों पर काम किया।

प्रमुख पदः

एसपी ट्रैफिक, नोएडा- यहां उन्होंने ट्रैफिक सुधार के कई अभिनव प्रयोग किए
एसपी, एटीएस और एसपी, एसटीएफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश
एसएसपी, एसटीएफ उत्तर प्रदेश झ पूरे प्रदेश में पेशेवर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की कमान

पीएसी ईस्ट जोन, प्रयागराज में तैनाती के बाद 2024-2025 में उन्हें नोएडा का अपर पुलिस

बनवाया और 48 जवानों व उनके परिवारों का मुफ्त इलाज कराया। इस मॉडल को बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में अपनाया गया।

महिला सशक्तिकरण व सामुदायिक पुलिसिंग

मिशन शक्ति 5.0 के तहत नोएडा स्टेडियम में 'रन फॉर एम्पावरमेंट'का आयोजन उनके नेतृत्व में हुआ। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान, कल्याणकारी योजनाएं और चौपालों के माध्यम से समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। 10 जून 2025 को नोएडा सिटीजन फोरम के साथ बैठक में उन्होंने 'सामुदायिक पुलिसिंग, नाइट पेट्रोलिंग, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और घरौंदा माफिया' पर चर्चा की और 15 दिन में एक्शन प्लान का आश्वासन दिया।

सम्मान और पहचान

राष्ट्रपति पुलिस पदक-वीरता

डीजीपी प्लेटिनम डिस्क

राज्य और केंद्र सरकार से कई प्रशंसा पत्र

तकनीक और इंटेलिजेंस के सहारे अपराध खत्म करने में माहिर अधिकारी के रूप में पहचान

कार्यशैली और नेतृत्व

उनकी छवि एक 'सख्त प्रशासक, तेजतर्रार अधिकारी' की है। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी बराबरी का सम्मान देते हैं। नोएडा में उनकी दूसरी पारी को लेकर पुलिस विभाग में सकारात्मक उत्साह है क्योंकि पहले भी यहां उनकी अपराध नियंत्रण नीतियों की सराहना हुई थी। वर्तमान में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जिले में बेहतर समन्वय के लिए उन्हें कानून व्यवस्था के साथ रिट सेल का दायित्व दिया है।

निष्कर्ष : आईपीएस राजीव नारायण मिश्रा का जीवन कर्तव्य, साहस और नवाचार का संगम है। अयोध्या में देश की रक्षा करने वाले जांबाज से लेकर नोएडा में ट्रैफिक और साइबर अपराध पर नियंत्रण करने वाले आधुनिक पुलिस अधिकारी तक, उनका सफर प्रेरणादायक है। कोविड में मानवता, महिलाओं के सशक्तिकरण और सामुदायिक पुलिसिंग पर उनका जोर उन्हें एक जनसेवी अफसर बनाता है। नोएडा की कानून व्यवस्था की कमान अब ऐसे अधिकारी के हाथों में है जिनकी पहचान 'जीरो टॉलरेंस' और 'टेक्नोलॉजी के साथ पुलिसिंग' है। ऐसे देश के बीर जवानों की सेवा के लिए राष्ट्र समाज परिवार हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करता है।

आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था बनाया गया ।वर्तमान में कानून व्यवस्था के साथ-साथ रिट सेल का पर्यवेक्षण भी हैं। सिंगापुर पुलिस की कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण भी लिया है।

प्रमुख उपलब्धियां और योगदान

ए.राष्ट्र की रक्षा में अदम्य साहस-अयोध्या हमला 2005

आईपीएस राजीव नारायण मिश्रा की सबसे बड़ी पहचान 5 जुलाई 2005 को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि पर हुए आतंकी हमले में उन्होंने प्राणों की परवाह न करते हुए सीआरपीएफ के साथ आतंकवादियों से सीधा मोर्चा लिया और हमले में शामिल सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से एके-47, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर जैसी बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद हुई थी। इस वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति के पुलिस पदक-वीरता से सम्मानित किया। इसी कारण उन्हें 'अयोध्या के रणबांकुरे' और 'योगी के भरोसेमंद अफसर' भी कहा जाता है।'

अपराध नियंत्रण में सख्त प्रशासक की छवि

वे एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय अधिकारी माने जाते हैं। एसटीएफ में रहते हुए उन्होंने 37,000 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का पदार्फाश किया और साइबर अपराधियों को जेल पहुंचाया। एटीएस में रहते हुए कई आतंकी साजिशों को विफल किया। एसएसपी, एसटीएफ रहते हुए उन्होंने अभ्यस्त और पलायित अपराधियों को उनके 'अंतिम अंजाम' तक पहुंचाया। नोएडा जैसे हाई-प्रोफाइल क्षेत्र में उनकी तैनाती को इस बात का संकेत माना गया कि राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी।

ट्रैफिक और टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव

राजीव नारायण मिश्रा अभिनव प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। एसपी ट्रैफि क नोएडा रहते हुए उन्होंने 'उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर कैमरों के माध्यम से ऑटोमेटिक चालान प्रणाली' शुरू की। इसका परिणाम ये हुआ कि सड़क दुर्घटनाओं और मृतकों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आई। वर्तमान में भी उनसे ट्रैफिक व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और शहरी कानून व्यवस्था में बड़े निर्णयों की उम्मीद है।

कोविड काल में मानवता की मिसाल

कोरोना की पहली लहर में जब लोग परेशान थे, तब उन्होंने अपने पैक्ट में एल-1 हॉस्पिटल

@ राष्ट्र समाज

भारत-बांग्लादेश संबंधों की नई परीक्षा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिसंबर 2026 में स्वदेश लौटने की घोषणा केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति, लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन गया है। जिस समय बांग्लादेश की राजनीति सत्ता परिवर्तन, वैचारिक ध्रुवीकरण और संस्थागत अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, उसी समय शेख हसीना ने यह घोषणा कर राजनीतिक विमर्श को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। उनका यह कहना कि 'गिरफ्तारी, जेल या मृत्यु का भय भी उन्हें अपने देश लौटने से नहीं रोक सकता', उनके समर्थकों के लिए भावनात्मक आह्वान है तो विरोधियों के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती। बांग्लादेश में पिछले वर्ष सत्ता परिवर्तन के बाद जो राजनीतिक वातावरण बना, उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और राजनीतिक सहिष्णुता पर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा शेख हसीना के विरुद्ध सुनाया गया फैसला और उसके बाद उनके समर्थकों पर बढ़ती कार्रवाइयों ने यह संकेत दिया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे प्रतिशोध की राजनीति में बदलती जा रही है। हाल ही में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे पूर्व क्रिकेट कप्तान साकिब अल हसन के घर पर हुआ हमला भी इस बात का संकेत है कि राजनीतिक असहमति अब सामाजिक तनाव का रूप लेने लगी है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के एक करीबी सहयोगी द्वारा शेख हसीना को 'तुरंत लौटकर सामना करने' की चुनौती देना बताता है कि बांग्लादेश का राजनीतिक वातावरण अभी भी सामान्य नहीं हुआ है।

लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल या नेता से असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति का समाधान न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया और स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए। यदि किसी नेता की लोकप्रियता का उत्तर प्रतिबंध, दमन या भय के वातावरण से दिया जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होती है। शेख हसीना की वापसी को केवल एक व्यक्ति की वापसी के रूप में नहीं, बल्कि

लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि अवामी लीग को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश होती है, तो यह बांग्लादेश के लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाएगा। वास्तविकता यह भी है कि बांग्लादेश की राजनीति व केवल अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनललिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बीच सत्ता संघर्ष तक सीमित नहीं रह गई है। अब यह संघर्ष राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान, 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत और भविष्य की वैचारिक दिशा का भी बन चुका है। अवामी लीग स्वयं को मुक्ति संग्राम की मूल चेतना का प्रतिनिधि बताती है, जबकि बीएनपी भी अब उसी विरासत पर अपना दावा प्रस्तुत कर रही है। इतिहास की इस प्रतिस्पर्धी व्याख्या ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और गहरा किया है। ऐसी परिस्थितियों में शेख हसीना की वापसी केवल राजनीतिक समीकरण नहीं बदलेगी, राष्ट्रीय विमर्श की दिशा भी प्रभावित करेगी।

इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल दो पड़ोसी देशों के रिश्ते नहीं हैं, बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा, आर्थिक सहयोग और सामरिक हितों पर आधारित हैं। पिछले डेढ़ दशक में दोनों देशों के संबंधों में अभूतपूर्व निकटता आई, जिसका एक बड़ा आधार शेख हसीना सरकार और नई दिल्ली के बीच बना विश्वास था। सीमा विवादों का समाधान, ऊर्जा सहयोग, संपर्क परियोजनाएं, आतंकवाद के विरुद्ध साझा कार्रवाई तथा पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन ने इस विश्वास की नई परीक्षा शुरू कर दी है। नई दिल्ली ने एक ओर शेख हसीना को सुरक्षा और आश्रय दिया है, वहीं दूसरी ओर उसने ढाका की नई सरकार से संवाद भी जारी रखा है। यही परिपक्व कूटनीति का परिचायक है। भारत के सामने चुनौती किसी एक राजनीतिक दल के साथ खड़ा दिखाई देने की नहीं, बल्कि पूरे बांग्लादेश के साथ स्थायी और संतुलित संबंध बनाए रखने की है। इसी संदर्भ में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। यदि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इसमें भाग लेते हैं और भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ सकारात्मक संवाद होता है, तो दोनों देशों के बीच हाल के तनावों को कम करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह केवल औपचारिक शिखर बैठक नहीं होगी, दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का अवसर भी होगी। भारत को इस मंच का उपयोग केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सुरक्षा सहयोग पर भी स्पष्ट संवाद स्थापित करना चाहिए।

भारत के सामने अनेक जटिल प्रश्न भी हैं। गंगा जल संधि के नवीनीकरण, तीस्ता जल बंटवारे, सीमा-पार व्यापार, अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा तथा शेख हसीना के प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करेंगे। इनमें किसी भी विषय पर भावनात्मक या राजनीतिक प्रतिक्रिया के बजाय कानूनी, कूटनीतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। विशेष रूप से प्रत्यर्पण का प्रश्न केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीतिक परिस्थितियों से भी जुड़ा हुआ है। भारत को अपनी संधियों, न्यायिक प्रक्रियाओं और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। दूसरी ओर बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव भी नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान सरकार के शुरूआती महीनों में चीन के साथ बढ़ते संपर्क और सामरिक महत्व की परियोजनाओं पर समझौते इस बात का संकेत हैं कि ढाका अपनी विदेश नीति में संतुलन साधने का प्रयास कर रहा है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिस्पर्धा की मानसिकता के बजाय विश्वास और विकास की साझेदारी को प्राथमिकता दे। यदि भारत आर्थिक सहयोग, निवेश, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर विकसित करता है, तो दोनों देशों के संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं।

शेख हसीना की वापसी का प्रश्न अंततः बांग्लादेश के लोकतांत्रिक चरित्र की परीक्षा है। यदि उन्हें निष्पक्ष राजनीतिक अवसर मिलता है, तो जनता स्वयं तय करेगी कि भविष्य का नेतृत्व किसे सौंपना है। यदि राजनीतिक प्रतिशोध, दमन और हिंसा का वातावरण बना रहता है, तो इससे न केवल बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साख प्रभावित होगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत को इस पूरे घटनाक्रम में संयम, संतुलन और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। न तो उसे किसी आंतरिक राजनीतिक विवाद का पक्षकार बनना चाहिए और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा करनी चाहिए। भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य एक स्थिर, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध पड़ोस होना चाहिए। यही उसकी सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए सबसे अनुकूल स्थिति होगी।

आज आवश्यकता किसी राजनीतिक विजय की नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता की है। बांग्लादेश को यह सिद्ध करना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं, बल्कि विपक्ष के सम्मान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक सहिष्णुता का भी नाम है। वहीं भारत को यह दिखाना होगा कि वह पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को व्यक्तियों के बजाय संस्थागत विश्वास, पारस्परिक सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ाने में सक्षम है। दिसंबर 2026 में यदि शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटती हैं, तो वह केवल एक नेता की वापसी नहीं होगी, वह बांग्लादेश के लोकतंत्र, भारत की कूटनीतिक परिपक्वता और दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिरता की एक साथ परीक्षा होगी। यदि इस चुनौती को संवाद, लोकतांत्रिक मयार्दा और विवेकपूर्ण कूटनीति के साथ संभाला गया, तो यह संकट दोनों देशों के संबंधों में एक नए विश्वास और नई शुरूआत का आधार भी बन सकता है। यही समय की सबसे बड़ी मांग है। यहां एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि शेख हसीनाा के बांग्लादेश यानी वतन-वापसी से वहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को नई धार मिलेगी या फिर वह और अधिक बंट जाएंगी?

सुप्रीम कोर्ट का वकील कैसे बनें-चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

@ राष्ट्र समाज

परिचयः

12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले किसी भी छात्र के लिए सबसे कठिन निर्णयों में से एक है करियर की योजना बनाना और उसे लागू करना। बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के सामने कई भ्रम, गलत धारणाएं और विकल्प मौजूद होते हैं। हालांकि बारहवीं के बाद करियर के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इस लेख में हम कानून के क्षेत्र में करियर, विशेष रूप से भारत में सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के तरीके पर चर्चा करेंगे। भारत की सर्वोच्च अदालत होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय का वकील बनने की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। इस लेख में हम भारत में सर्वोच्च न्यायालय का वकील बनने के लिए आवश्यक चरण-दर-चरण प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे।

चरण 1-विधि की पढ़ाई करने की पात्रता के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना

एक बार जब कोई उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने का फैसला कर लेता है, तो उसे अधिकांश लॉ कॉलेजों में दाखिले के लिए कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। कुछ कॉलेज 45% से कम अंकों पर भी दाखिले स्वीकार करते हैं, लेकिन अधिकतर कॉलेजों में न्यूनतम पात्रता मानदंड 45% ही माना जाता है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवार सीएलएटी या अन्य निजी कॉलेजों के माध्यम से 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम (बीएएलएलबी/बी.कॉम/ एलएलबी/ बीएससी.एलएलबी आदि) में दाखिला ले सकते हैं। स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवार 3 वर्षीय एलएलबी कार्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन पत्र भरकर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे।

चरण 2-विधि महाविद्यालय में दाखिला लेना

कॉलेज में दाखिला लेने के बाद, पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान ही उम्मीदवार को वकीलों या कानूनी फर्मों के साथ इंटर्नशिप करना अनिवार्य होता है ताकि उसे व्यावहारिक ज्ञान व क्षेत्र का अनुभव प्राप्त हो सके। ये इंटर्नशिप एक मजबूत आधार बनाने व पाठ्यक्रम समाप्त होते ही उसे उद्योग के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जमीनी स्तर से शुरूआती स्तर पर सीखना ही इन इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य है। इंटर्नशिप करने से संस्कृति और व्यावसायिकता

सीखने का अतिरिक्त लाभ भी मिलता है।

चरण 3-भारतीय बार परिषद में पंजीकरण

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद , उम्मीदवार को बार काउंसिल में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। भारतीय अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार, अदालत में वकालत करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होने के बाद, वकील अधिवक्ता बन जाते हैं और भारत की अदालतों में वकालत करने के योग्य हो जाते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य की बार काउंसिल में पंजीकरण करा सकते हैं, जहां आप वकालत करना चाहते हैं।

चरण 4-कनिष्ठ सहायक बनें

अब जबकि आप विधिवत वकालत करने के योग्य हैं व आपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही वकालत करने का निश्चय कर लिया है, तो सबसे आसान तरीका है किसी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के कनिष्ठ सहायक बनना। इससे न केवल आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय में काम करने का अवसर मिलेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को समझें, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ता के रूप में आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी। भारत के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्ठ सहायक को बुनियादी कार्यवाही सीखने और सर्वोच्च न्यायालय की कार्य संस्कृति से परिचित होने में सहायता करते हैं।

चरण 5-अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करें

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) हर साल अखिल भारतीय बार परीक्षा(एआईबीई) आयोजित करती है। भारत में कानून की अदालतों में वकालत करने के इच्छुक प्रत्येक वकील को अखिल भारतीय बार परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। यह परीक्षा 100 अंकों की होती है और बीसीआई द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है।

इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिन्हें 3 घंटे 30 मिनट की अवधि में हल करना होता है इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, उम्मीदवार देश भर की किसी भी अदालत में वकील के रूप में वकालत करने के योग्य हो जाता है।

चरण 6-अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य करना

अब जबकि आप भारत की अदालतों में वकालत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी वकालत शुरू करने से पहले कुछ अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। यह सलाह दी जाती है कि आप अपने कानूनी करियर की शुरूआत अधीनस्थ न्यायालयों, जैसे जिला न्यायालयों या उच्च न्यायालयों से करें। अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत करने और करियर शुरू करने से दोहरे लाभ मिलते हैं: इससे आपको जमीनी स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है, अदालती प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है और साथ ही आपको ऐसा अनुभव भी मिलता है जिसका उपयोग आप बाद में सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए कर सकते हैं।

चरण 7-अनुभव प्राप्त करें

जिला न्यायालयों या उच्च न्यायालयों में से किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में 5 वर्ष का अनुभव पूरा करने के बाद, उम्मीदवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से वकालत करने से पहले किसी सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता के अधीन प्रशिक्षु के रूप में कार्य करना आवश्यक है। संक्षेप में, विधि में डिग्री पूरी करने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए न्यूनतम 6 वर्ष का समय लगेगा।

चरण 8-एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करें

भारत का सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा (एओआर परीक्षा) आयोजित करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने के इच्छुक हैं। यह परीक्षा अधिवक्ताओं के ज्ञान, कौशल और योग्यता की जांच करने और यह जानने के लिए आयोजित की जाती है कि वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए कितने योग्य हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद, उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सदस्य के रूप में अपना पंजीकरण कराकर सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए पात्र हो जाता है।

चरण 9-पदभार ग्रहण करें

एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर से 10 मील के दायरे में एक कार्यालय स्थान के लिए पंजीकरण कराना होगा और अपने कार्यालय में एक पंजीकृत कार्यालय क्लर्क नियुक्त करना होगा। उपरोक्त सभी औपचारिकताओं को पूरा करने पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता (एओआर) के रूप में स्वीकार करते हैं।

चरण 10-भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत शुरू करें

इसके बाद आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से वकालत करने और अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने तथा कानून के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के अनुसार मामलों को उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे।

निष्कर्ष:

एक बार जब आप अपना करियर शुरू कर लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में अपना स्वतंत्र कार्यालय संभाल लेते हैं, तो आपको यह याद रखना चाहिए कि कानूनी क्षेत्र में सफलता रातोंरात नहीं मिलती और आपको धैर्य और लगन के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसे दिन और सप्ताह भी आ सकते हैं जब आपको पर्याप्त या अच्छे भुगतान वाले मुवक्किल न मिलें, लेकिन निराशा में हार मानना कभी भी समाधान नहीं है। यदि हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष और सबसे सफल वकीलों की सूची देखें, तो हम उनके अनुभवों से भी सीख सकते हैं कि कैसे एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और निरंतरता ने उन्हें लंबे समय में सफल होने में मदद की। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें कानून के क्षेत्र में, विशेष रूप से भारत के सुप्रीम कोर्ट में, शुरूआती सफलता नहीं मिली है और कड़ी मेहनत वह बीज है जिसे आप बोते हैं और बाद में सफलता प्राप्त करते हैं।

गाज़ियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में खुला बीकानेरवाला का नया स्टोर

स्वाद और संस्कृति का नया संगम

@ राष्ट्र समाज

गाज़ियाबाद। देश की सांस्कृतिक राजधानी दिल्ली- एनसीआर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में से एक राजनगर एक्सटेंशन अब स्वाद के मामले में भी एक नई पहचान बनाने जा रहा है। देश के जाने-माने और भरोसेमंद फूड ब्रांड 'बिकानेर वाला' ने अपने नए आउटलेट का भव्य उद्घाटन 2 अगस्त 2026, रविवार को द हब, राज नगर एक्सटेंशन, नूर नगर, गाज़ियाबाद में किया। दोपहर 2 बजे हुए इस उद्घाटन समारोह में स्थानीय गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। उद्घाटन के साथ ही बीकानेर वाला ने घोषणा की कि यह स्टोर न केवल स्वाद देगा, बल्कि भारतीय खान-पान की घर जैसी शुद्धता और परंपरा को भी आगे बढ़ाएगा।

राजनगर एक्सटेंशनः नई कॉलोनियों का नया स्वाद केंद्र

राजनगर एक्सटेंशन पिछले 5-6 वर्षों में गाज़ियाबाद का सबसे तेजी से बसने वाला क्षेत्र बना है। हजारों परिवार यहां नए घरों में शिफ्ट हुए हैं। इस क्षेत्र में अभी तक बड़े और ब्रांडेड फूड आउटलेट्स की कमी महसूस की जा रही थी। बीकानेरवाला का आना इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि अब क्षेत्र के लोगों को शुद्ध शाकाहारी, गुणवत्तापूर्ण और हाइजीनिक भोजन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। द हब, मॉल राजनगर एक्सटेंशन का प्रमुख कमर्शियल हब है। यहीं पर बीकानेरवाला का यह नया स्टोर खुला है, जो आने-जाने वालों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है।

बीकानेरवालाः 60 साल की विरासत, शुद्धता की पहचान बीकानेरवाला नाम सुनते ही आंखों के सामने भुजिया, रसगुल्ले, समोसे और कचौड़ी की तस्वीर आ जाती है। 1950 में बीकानेर से शुरू हुआ यह सफर आज देश-

विदेश में 150 से ज्यादा आउटलेट्स तक पहुंच चुका है।

बीकानेरवाला की सबसे बड़ी पहचान है: 'शुद्धता और स्वाद' कंपनी आईएसओ 22000 और एफएसएसएआई प्रमाणित है। यहां इस्तेमाल होने वाला तेल, घी और मसाले सभी उच्च गुणवत्ता के होते हैं। भीड़-भाड़ वाले समय में भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है।

नए स्टोर के मैनेजर ने बताया: 'हमारा उद्देश्य राजनगर एक्सटेंशन के परिवारों को घर जैसा खाना देना है। त्योहारों पर स्पेशल मिठाई, रोज के लिए थाली और बच्चों के लिए फास्ट फूड-सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा।'

उद्घाटन के दिन क्या खास रहा?

2 अगस्त को उद्घाटन के दिन स्टोर को गुब्बारों व फूलों से सजाया गया था। दोपहर2बजे बीकानेर वाला के निर्देशक श्याम सुंदर अग्रवाल ने और साथ में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर फीता काटकर स्टोर का उद्घाटन किया गया।

खास आकर्षण

उद्घाटन ऑफर: पहले ग्राहकों को मिठाई का डिब्बा मुफ्त
फूड फेस्टिवल: राजस्थानी थाली, चाट कॉर्नर और साउथ इंडियन काउंटर पर 20% की छूट
बच्चों के लिए: फ्री आइसक्रीम और गेम जोन
लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई परिवार उद्घाटन के दिन ही पूरे परिवार के साथ खाने पहुंचे।

स्थानीय निवासी श्री राकेश शर्मा ने कहा: 'राजनगर एक्सटेंशन में अब तक ढंग का मिठाई का ब्रांड नहीं था। बीकानेरवाला के आने से त्योहारों पर हमें बहुत सुविधा होगी। शुद्धता की गारंटी है।'

4. मेन्यू में क्या मिलेगा?

नए बीकानेरवाला स्टोर में 4 सेक्शन बनाए गए हैं:

मिठाई काउंटर: बेसन लड्डू, मोतीचूर लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी की 50+ वैरायटी
नमकीन सेक्शन: भुजिया, काजू कतली, मठरी, गाठिया
रेस्तरां: थाली, चाट, डोसा, पाव भाजी, चाइनीज और पिज्जा
बेकरी: केक, पेस्ट्री, ब्रेड और कुकीज

खास बात यह है कि यहां जैन फूड और फास्टिंग थाली की भी व्यवस्था है, जो क्षेत्र के कई परिवारों की मांग थी।

रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

इस एक स्टोर से लगभग 40-50 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इसमें कुक, वेटर, काउंटर स्टाफ और डिलीवरी बॉय शामिल हैं। कंपनी ने ज्यादातर स्टाफ स्थानीय स्तर से ही रखा है।

इसके अलावा आसपास के दूध, सब्जी और पैकेजिंग के विक्रेताओं को भी बड़ा बाजार मिलेगा। इससे राजनगर एक्सटेंशन की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

त्योहारों पर खास तैयार

15 अगस्त और जन्माष्टमी नजदीक हैं। बीकानेरवाला प्रबंधन श्री श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि इन त्योहारों के लिए स्पेशल पैकिंग की तैयारी चल रही है।

जन्माष्टमी पर: माखन-मिश्री, पंजीरी, मावा पेड़ा
15 अगस्त पर:तिरंगा बर्फी और देशभक्ति थीम वाली मिठाई के साथ सभी ग्राहको को 15 अगस्त,जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी,तीज उत्सव, दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

संपर्क और डिलीवरी

ग्राहक स्टोर पर आकर भी खा सकते हैं और घर बैठे डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं।

पता: द हब, राज नगर एक्सटेंशन, नूर नगर, गाज़ियाबाद
संपर्क: +91 9311125587
समय:सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक

निष्कर्ष:

बीकानेरवाला का राजनगर एक्सटेंशन में आना सिर्फ एक दुकान खुलना नहीं है। यह इस क्षेत्र के विकसित होने, यहां के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने और शुद्ध खान-पान की मांग बढ़ने का प्रतीक है। उम्मीद है कि यह स्टोर क्षेत्रवासियों को स्वाद के साथ-साथ 'राष्ट्र समाज' की भावना-शुद्धता, संस्कार व सेवा-भी देगा।

स्वतंत्रता दिवस

15 अगस्त

त्याग, तिरंगे और तिरंगा का संकल्प

15 अगस्त 1947 का दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। लगभग 200 साल की गुलामी के बाद जब लाल किले की प्राचीर से पंडित नेहरू ने 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' कहा, तब करोड़ों भारतीयों की आंखों में आजादी के आंसू थे।

स्वतंत्रता दिवस का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और लाखों अज्ञात शहीदों का बलिदान याद आता है। उन्होंने हंसते-हंसते फांसी चूम ली ताकि हम आजादी की खुली हवा में सांस ले सकें।

आज 2026 में 79वां स्वतंत्रता दिवस 'विकसित भारत 2047' के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। आईएनएस विक्रांत, तेजस, ब्रह्मोस आज भारत की ताकत हैं। 'आयात से निर्यात' तक का सफर इसी आजादी की देन है।

इस दिन का महत्व सिर्फ सरकारी परेड तक सीमित नहीं। हर स्कूल, हर गली, हर घर में तिरंगा फहरता है। 'हर घर तिरंगा' अभियान ने देशभक्ति को जन-जन तक पहुंचाया। स्वतंत्रता का असली मतलब है-गरीबी से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, और नारी की असुरक्षा से आजादी।

प्रमोद जी,

'राष्ट्र समाज' के पाठकों के लिए संदेश यही है: आजादी मिली है, इसे बचाना भी हमारा कर्तव्य है।

जय हिंद।

रक्षा बंधन

रक्षा का धागा, रिश्तों की शक्ति

रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई जीवनभर रक्षा का वचन देता है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ भाई-बहन तक सीमित नहीं है।

पौराणिक कथा कहती है कि रानी कुंती ने कृष्ण को राखी बांधी थी। इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। इसीलिए ये त्यौहार 'सुरक्षा और समर्पण' का प्रतीक है।

आज के समय में रक्षा बंधन का सामाजिक महत्व और बढ़ गया है। सीमा पर खड़े जवानों को बहनें राखी भेजती हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी स्कूल की बच्चियां राखी बांधती हैं। ये बताता है कि देश की रक्षा ही सबसे बड़ा रिश्ता है।

रक्षा बंधन हमें सिखाता है-रिश्ते खून से नहीं, कर्तव्य से बनते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों की, एक डॉक्टर अपने मरीजों की, और एक सैनिक देश की रक्षा करता है। सब अपनी-अपनी जगह राखी बांध रहे हैं।

आज ऑनलाइन राखी और वीडियो कॉल का जमाना है, पर भावना वही है। ये त्यौहार हमें परिवार, समाज और राष्ट्र की एकता से जोड़ता है।

गणेश चतुर्थी

विघ्नहर्ता से विघ्न मुक्त भारत तक

'गणपति बप्पा मोरया!'10 दिन तक गूंजने वाला ये नारा सिर्फ उत्सव नहीं, आस्था का महापर्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश जी को 'प्रथम पूज्य' और 'विघ्नहर्ता' कहा जाता है। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले उनकी पूजा होती है। इसका महत्व ये है कि जीवन में आने वाली हर बाधा को बुद्धि और धैर्य से दूर किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजों के समय सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू किया था ताकि लोग एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ें। आज भी ये त्यौहार सामाजिक एकता का प्रतीक है।

2026 में इको-फ्रेंडली गणेश की मूर्ति का चलन बढ़ा है। मिट्टी की मूर्ति, तालाब में विसर्जन-ये प्रकृति से हमारा जुड़ाव दिखाता है। डीडीए और नगर निगम भी 'ग्रीन गणेश' अभियान चला रहे हैं।

गणेश जी का बड़ा पेट हमें सिखाता है-अच्छे-बुरे सबको पचाना सीखो। छोटी आंखें-सूक्ष्मता से देखो। बड़ा कान-सबकी सुनो। और चूहे की सवारी-इच्छाओं पर नियंत्रण।

संदेश:

जैसे गणेश जी हर घर में आते हैं, वैसे ही विकास हर घर तक पहुंचे। नया भारत बनाने में हर विघ्न को दूर करें।

गणपति बप्पा मोरया!

जन्माष्टमी

धर्म की स्थापना और कर्म का संदेश

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अंधेरी रात, तेज बारिश, और वासुदेव जी की टोकरी में बंधे कृष्ण- ये दृश्य हर साल हमें याद दिलाता है कि अधर्म पर धर्म की जीत जरूर होती है।

जन्माष्टमी का महत्व गीता में है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कृष्ण ने कहा: 'कर्म करो, फल की चिंता मत करो'। आज के युवा, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी- सबके लिए ये सबसे बड़ा जीवन मंत्र है। कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, एक आर्दश राजनीतिज्ञ, मित्र, गुरु और योगी थे। उन्होंने सुदामा को मित्रता सिखाई, गोपियों को प्रेम, और अर्जुन को युद्ध। मथुरा, वृंदावन, द्वारका में इस दिन झांकियां सजती हैं। दही-हांडी फोड़कर युवा बताते हैं कि टीमवर्क से ऊंचे लक्ष्य भी हासिल होते हैं। दिल्ली-एनसीआर में इस्कॉन मंदिर की झांकियां लाखों लोग देखने आते हैं।

आज के समय में जन्माष्टमी हमें सिखाती है, भ्रष्टाचार रूपी कंस को हराना है, नारी सम्मान की रक्षा करनी है, और 'गीता' के ज्ञान से राष्ट्र निर्माण करना है।

भगवान कृष्ण ने कहा था, 'जब-जब धर्म की हानि होगी, मैं अवतार लूंगा'। 2026 के भारत में ये संदेश और प्रासंगिक है। हम सब अपने-अपने क्षेत्र में धर्म के लिए काम करें।

गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने हेतु धर्म जागरण परिषद ने डीसी कंझावाला को ज्ञापन सौंपा

@ राष्ट्र समाज

गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर धर्म जागरण परिषद के बैनर तले गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने और गौ रक्षा कानून लागू कराने की मांग को लेकर चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत रोहणी सेक्टर 37 में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी विजय प्रधान ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर जुलूस निकाला और गौ माता का पूजन किया। अभियान में उपस्थित लोगों ने गौ रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम के बाद अभियान के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी कंझावाला से भेंट कर क्षेत्र में गौशालाओं की कमी, आवारा गौवंश की समस्या और गौ तस्करी जैसी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि गौ रक्षा के लिए सख्त कानून बनाया जाए और गौशालाओं के लिए पर्याप्त बजट और जगह आवंटित किया जाए। धर्म जागरण परिषद के प्रान्त गौ रक्षा प्रमुख विजय प्रेमी जी ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल के सदस्यो के साथ मिलकर जो डीसी को ज्ञापन सौंपा था , उसे गंभीरता से लेते हुए शीघ्र उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान 27 जुलाई 2026 से 27 अगस्त 2026 तक देशभर में चलाया जा रहा है। जिसे देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में इस अभियान का संचालन करने के लिए कार्य जारी हैं।

BTW

Delivering Taste, Quality & Legacy

AT EVERY STEP

RETAIL

As a pure vegetarian restaurant, we serve a wide variety of multi-cuisine dishes and are especially known for our chaat and snacks. We operate 20 QSR outlets across Delhi NCR and Mohali. Our stores also offer a comprehensive selection of sweets and gifting options.

FMCG

Our FMCG range has over 1000 SKUs, available across major modern outlets, e-commerce platforms, army canteens, and police canteens. We also manufacture material for several esteemed brands through private labelling, like Unibic, Big Basket, Vishal Mega Mart etc.

CATERING

We are one of India's largest Chaat caterers and offer catering services across the globe. On average, we serve around 75 functions each wedding season, maintaining our quality and legacy at every event.

For More Information

01164646464 | customercare@btwindia.com | www.btwindia.com

जौंती में मां बगलामुखी शक्तिपीठ

आस्था, सेवा, समर्पण और सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण की दिव्य गाथा

@ राष्ट्र समाज

भारत की पावन भूमि पर जब भी धर्म, संस्कृति और सेवा का संगम होता है, तब इतिहास स्वयं एक नया अध्याय लिखता है। माँ बगलामुखी की दिव्य कृपा और भक्तों की अटूट श्रद्धा से ऐसा ही एक अध्याय दिल्ली की पवित्र भूमि जौंती में माँ बगलामुखी शक्तिपीठ के रूप में साकार हो रहा है।

17 जुलाई 2025 को वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ सम्पन्न भूमि पूजन ने इस दिव्य शक्तिपीठ की आधारशिला रखी। इसके बाद अत्यंत अल्प समय में श्रद्धालुओं के सहयोग, सेवा और समर्पण से मंदिर निर्माण ने अभूतपूर्व गति प्राप्त की। आज यह शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, साधना, सेवा और सामाजिक चेतना का एक जीवंत केंद्र बन चुका है। इसी दिव्य यात्रा के

मध्य 22 मार्च 2026, रविवार का वह ऐतिहासिक दिवस आया, जिसने इस अभियान को एक नई दिशा प्रदान की।

श्रद्धेय विजय गर्ग जी सिविल लाइन्स स्थित निवास पर तीनों देवियों—श्री देवसर वाली माता, श्री पहाड़ी वाली माता एवं श्री भोजावाली माता—की पावन ज्योति रथ यात्रा पहुँची। विद्वान आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य माँ बगलामुखी के दिव्य हवन कुण्ड के समक्ष एक ऐतिहासिक संकल्प लिया गया कि दिल्ली के जौंती स्थित माँ बगलामुखी शक्तिपीठ परिसर में तीनों देवियों का एक भव्य एवं दिव्य मंदिर निर्मित किया जाएगा। यही संकल्प आगे चलकर सनातन संस्कृति के एक नए अध्याय का आधार बना।

इस संकल्प की पूर्णता की दिशा में 19 जुलाई 2026 का दिन भी इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित हो गया, जब देवसर माता धाम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हजारों श्रद्धालुओं, संत-महात्माओं एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर भिवानी से आए सैकड़ों परिवारों ने अपनी श्रद्धा और समर्पण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने हाथों से एक-एक ईंट अर्पित की। यह केवल ईंटों का समर्पण नहीं था, बल्कि अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर धरोहर के निर्माण का संकल्प था। महाराजा अग्रसेन की 'एक ईंट झ्र एक सहयोग' की परंपरा उस दिन साकार होती हुई दिखाई दी।

'हरियाणा की गौरवशाली भूमि भिवानी, जिसे श्रद्धापूर्वक 'छोटी काशी' कहा जाता है, सदियों से धर्म, वीरता, समाजसेवा और सनातन संस्कृति की पहचान रही है। इसी पुण्यभूमि पर स्थित देवसर धाम लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। अब उसी दिव्य शक्ति का विस्तार दिल्ली की जौंती स्थित मां बगलामुखी शक्तिपीठ में हो रहा है, जहां भिवानी की लोकआस्था और दिल्ली की आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम साकार हो रहा है।'

आज इस पावन परिसर में मंदिर निर्माण के साथ-साथ सेवा के अनेक आयाम भी निरंतर विकसित हो रहे हैं। यहाँ गौशाला पूर्ण रूप से संचालित है, जहाँ गोमाताओं की सेवा, संरक्षण और संवर्धन का कार्य प्रतिदिन श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जा रहा है। यह गौशाला केवल पशु संरक्षण का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, करुणा और सेवा भाव का जीवंत प्रतीक है।

इसके साथ ही श्रद्धालुओं, संतों एवं देश-विदेश से आने वाले अतिथियों की सुविधा के लिए देवसर धाम आश्रम का निर्माण भी प्रगति पर है। इस आश्रम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 36 सेंट्रलाइज्ड एयर-कंडीशंड कक्ष निर्मित किए जा रहे हैं, जहाँ साधना, सत्संग, आध्यात्मिक प्रवास और धार्मिक आयोजनों के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था उपलब्ध होगी। भविष्य में यह आश्रम अध्यात्म, संस्कृति और सेवा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

यह केवल घटनाओं का व्यखान नहीं है, बल्कि श्रद्धा, सेवा, त्याग और सामूहिक सहभागिता की उस प्रेरणादायी यात्रा का दस्तावेज है, जिसने एक संकल्प को साकार होते हुए इतिहास में परिवर्तित कर दिया। इसमें माँ बगलामुखी शक्तिपीठ की स्थापना से लेकर उसके तीव्र निर्माण, भिवानी की गौरवशाली विरासत, देवसर धाम की प्राचीन आस्था, 22 मार्च 2026 के ऐतिहासिक संकल्प, 19 जुलाई 2026 के भव्य भूमि पूजन, मंदिर निर्माण, गौसेवा तथा आश्रम निर्माण की सम्पूर्ण प्रेरक गाथा समाहित है।

हमारा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह दिव्य परिसर केवल एक मंदिर नहीं रहेगा, बल्कि सनातन संस्कृति, सेवा, गौसंरक्षण, आध्यात्मिक साधना और भारतीय जीवन मूल्यों का ऐसा केंद्र बनेगा, जहाँ से श्रद्धा और संस्कृति की ज्योति युगों-युगों तक सम्पूर्ण समाज का मार्ग आलोकित करती रहेगी।

हुमा कुरैशी ने जताई खुशी, फिल्म 'बयान' का आईएफएफएम में होगा ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर

अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने अपनी आगामी फिल्म 'बयान' के 2026 इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) में ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर को लेकर खुशी जाहिर की है। बिकास रंजन मिश्रा द्वारा लिखित और निर्देशित यह दमदार हिंदी पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा फेस्टिवल की आधिकारिक लाइन-अप का हिस्सा होगा और मेलबर्न में दर्शकों के सामने साल की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक पेश करेगा।'बयान' में हुमा रूही नाम की एक दृढ़ निश्चयी पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं, जो अपने पहले बड़े केस की जांच करती है। यह मामला एक प्रभावशाली धार्मिक गुरु पर लगे यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा है। जांच आगे बढ़ने के साथ रूही को सिस्टम की रुकावटों, गवाही देने से हिचकिचाने वाले लोगों और न्याय की राह में आने वाली कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।फिल्म के ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर को लेकर हुमा कुरैशी ने कहा, ₹'बयान' मेरे करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण और भावनात्मक रूप से संतोष देने वाली फिल्मों में से एक है। रूही एक ऐसी महिला है, जो हर तरह के दबाव के बावजूद अपने सिद्धांतों पर डटी रहती है। उसके इस सफर को निभाने ने मुझे एक कलाकार के रूप में कई नए अनुभव दिए।

43 की उम्र की प्रेग्नेंसी से खुद हैरान है ये हसीना

हॉलीवुड एक्ट्रेस ऐनी हैथवे जल्द ही तीसरी बार मां बनने वाली हैं। इन दिनों वह अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक इवेंट में बेबी बंप के साथ पहुंचीं ऐनी को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि उनका बेबी बंप नकली है। अब एक्ट्रेस ने इन लोगों को मजेदार अंदाज में जवाब दिया है। ऐनी अपनी फिल्मओक स्ट्रीट का अंत के प्रीमियर में पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने हैल्टर टॉप और लो-राइज जींस पहनी थी। उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा था। प्रीमियर के बाद कुछ टिकटॉक यूजर्स ने उनके बेबी बंप को फेक बताया। एक यूजर ने लिखा कि यह नकली लग रहा है। ऐनी ने इस पर कोई लंबी सफाई नहीं दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रीमियर से पहले का एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ₹नकली बाल, असली बेबी बंप, वीडियो में ऐनी के बालों को स्टाइल करके बड़ा पोनीटेल बनाया जा रहा था। आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर गोरी को मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया था और उसके बाद से काफी सारे इवेंट्स में भी दोनों साथ में ही नजर आते हैं।

संगीता ने वापस ली तलाक की अर्जी

थलपति विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम का रिश्ता टूटते टूटते बचा है और ऐसे में उनके बीच की सुलग उनके फैंस को काफी खुश कर रही है। जहां एक ओर फैंस में सेलिब्रेशन है तो वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस और थलपति विजय की गर्लफ्रेंड के तौर पर सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री तृषा कृष्णन के सोशल मीडिया पोस्ट जबरदस्त चचाओं में आ गए हैं। तृषा कृष्णन ने ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है जिसे विजय की पर्सनल लाइफ से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही कुछ लोग इसे पहले भी बता रहे हैं। दिसंबर 2025 में विजय और संगीता के तलाक की खबरें आई और फरवरी 2026 में संगीता ने विजय से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी थी। इसके बाद से विजय के शपथग्रहण से लेकर उनके बर्थडे पर हर जगह तृषा की मौजूदगी पर हर किसी की नजरे रही। तृषा कृष्णन ने ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है जिसे विजय की पर्सनल लाइफ से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही कुछ लोग इसे पहले भी बता रहे हैं। दिसंबर 2025 में विजय और संगीता के तलाक की खबरें आई और फरवरी 2026 में संगीता ने विजय से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी थी। इसके बाद से विजय के शपथ ग्रहण से लेकर उनके बर्थडे पर हर जगह तृषा की मौजूदगी पर हर किसी की नजरे रही। वहीं अब जब संगीता ने विजय से तलाक की अर्जी वापस ले ली है तो तृषा के ये पोस्ट टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं। तृषा ने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट किया उसमें लिखा था, 'इस उम्र में ड्रामा शर्मनाक है। जाओ कुछ पैसे कमाओ और शांति पाओ।'

Haldiram's
Banao
CHATPATE
PAL AUR
MEETHI
Yaadein!
TRADITION IN EVERY BITE,
HAPPINESS IN EVERY MOMENT.
Crafted with the finest ingredients and authentic recipes.
A perfect blend of savoury snacks and traditional sweets.
Hygienically prepared and packed for your safety.
Loved by millions for generations.
Perfect for every occasion, celebration and craving.
Bringing joy, taste and togetherness to your everyday moments.
From our kitchen to your heart – the Haldiram's promise.
REAL INGREDIENTS. GREAT TASTE. TIMELESS TRADITION.
Taste the tradition. Share the happiness.! | Shop Online @ www.haldiramsonline.com

RNI No. DELHIN/2014/56304

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
A MAHARATNA COMPANY

CELEBRATING

57

YEARS OF OUTSTANDING RESULTS,
FINANCING PROGRESS &
ENABLING TRANSFORMATION

FINANCIAL HIGHLIGHTS Q1 FY27

Net Worth	Net Interest Income	Net Profit
₹ 91,836 Crore	₹ 5,212 Crore	₹ 4,149 Crore

Follow us on: @RECLindia

E-mail: contactus@recindia.com | Website: www.recindia.nic.in